जनहितैषी

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

हिन्दी दैनिक

R.N.I. No. 63177/95 वर्षः29 अंकः222 दिनांकः23-07-2024 मंगलवार मूल्यः1 रूपया 50 पैसा पृष्ठः4 अहमदाबाद M

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ([illegible]) मंगलवार यानी 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री ने सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया

'नेम-प्लेट' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा कि बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। जब-जब इस देश में संविधान का उल्लंघन करने की कोशिश की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी भूमिका निभाता है।

इस साल जीडीपी 7 प्रतिशत रहने का अनुमान-वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री ने वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे किया पेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे सोमवार को सदन में पेश किया। इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर 6.5-7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और निजी निवेश में निरंतर गति से पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा मिला है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में 2023-24 में वास्तविक रूप से 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का राजकोषीय घाटा (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 1.6 प्रतिशत अंक बढ़ा।

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा है कि सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार प्रदाता बना हुआ है वहीं निर्माण क्षेत्र भी हाल ही में प्रमुखता से बढ़ रहा है, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की ओर की गई पहल नतीजा है। सर्वे के अनुसार खराब ऋणों की विरासत के कारण पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कम हुआ पर 2021-22 की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय बजट 2024-25 के अनावरण से ठीक पहले सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।

एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस

सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की प्रगति को और रफ्तार देने के लिए कृषि क्षेत्र इंजन का काम करेगा और सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण पर देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर रहा है। इसके साथ ही भारत को ड्रोन हब बनाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा।

बेरोजगारी घटी अब रोजगार पर जोर

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में साल 2030 तक औसतन सालाना करीब 78.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। हालांकि, इसमें साफ किया गया है कि देश में बेरोजगारी दर में गिरावट आई है और कोविड-19 महामारी के बाद से इसमें गिरावट आ रही है। 15 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2024 तक 6.7 प्रतिशत पर आ गई।

महिला स्वरोजगार में तेजी

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि महिला सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में तेजी आई है और सरकार के प्रयासों के चलते भारत की 57.3 प्रतिशत वर्कफोर्स सेल्फ-एम्प्लॉयड है और इसमें महिलाओं की भागीदारी उत्साह पैदा करने वाली है, जिसमें महिला सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट में जबर्दस्त बदलाव देखने को मिला है।

बैंकों की बैलेंस शीट दुरुस्त

इकोनॉमिक सर्वे में कंपनियों और बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत होने का दावा किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी के कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को लेकर काफी अनिश्चितता है। सर्वे रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया है कि एआई से प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन इसका कुछ सेक्टर्स में रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

विदेशी भारतीयों ने जमकर भेजा पैसा

सर्वे में ये भी जिक्र किया गया है कि जो भारतीय मूल के लोग दुनिया के तमाम देशों में रह रहे हैं, उन्होंने अपने परिजनों को जो पैसा भेजा है, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ा है। डेटा के मुताबिक, विदेश में बसे भारतीयों ने 2024 के दौरान देश में 124 अरब डॉलर का रेमिटेंस भेजा है। साल 2025 में इसके 129 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान।

भारतीय बाजार का प्रदर्शन शानदार

भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आर्थिक सर्वे में इसकी ग्रोथ स्टोरी में कैपिटल मार्केट की अहम भूमिका रही है। स्टॉक मार्केट ग्लोबल टेंशन और तमाम आर्थिक झटकों के बीच शानदार परफॉर्मिंग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, शेयर मार्केट का निफ्टी-50 इंडेक्स वित्त वर्ष 24 के दौरान 26.8 फीसदी की बढ़त में रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 8.2 फीसदी की गिरावट में था।

महंगाई में कमी की उम्मीद

इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में महंगाई दर में गिरावट आ सकती है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर के 4.5 फीसदी पर रहने का अनुमान जताया है।

कॉलेज पासआउट दो से में एक के पास रोजगार के लिए जरूरी योग्यता नहीं

आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का 65 प्रतिशत 35 वर्ष से कम उम्र का है, लेकिन उनमें से कई लोगों के पास आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। अनुमान बताते हैं कि लगभग 51.25 प्रतिशत युवा रोजगार के योग्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि सीधे कॉलेज से बाहर आने वाले लगभग दो में से एक युवा अब भी आसानी से रोजगार के योग्य नहीं है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले दशक में स्किल्ड युवाओं का प्रतिशत लगभग 34 प्रतिशत से बढक़र 51.3 प्रतिशत हो गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने बताया कि भारत में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति पर एनएसएसओ, 2011-12 (68वें दौर) की रिपोर्ट के अनुसार, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में लगभग 2.2 प्रतिशत ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वहीं, 8.6 प्रतिशत ने गैर-औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना 78.5 लाख रोजगार सृजन की जरूरत

आर्थिक सर्वे के अनुसार देश में बढ़ते मानव संसाधन को काम मुहैया कराने के लिए गैर कृषि क्षेत्र में 2030 तक सालाना 78.5 लाख रोजगार सृजन करने की जरूरत है। सर्वे में कहा गया है कि कामकाज की उम्र का हर व्यक्ति नौकरी ही नहीं करेगा। उनमें से कुछ स्वरोजगार भी करेंगे और कुछ लोग नियोक्ता भी बनेंगे। सर्वे में कहा गया है कि देश का आर्थिक विकास नौकरियों से ज्यादा लोगों को आजीविका मुहैया कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी स्तर के सरकारों और निजी क्षेत्र को भी इस में योगदान देना होगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार कृषि क्षेत्र का श्रम बल जो 2023 में 45.8 प्रतिशत है वह 2047 तक धीरे-धीरे घटकर 25 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। इसलिए 2030 तक हमें गैर कृषि क्षेत्र में सालाना करीब 78.5 लाख रोजगार मुहैया कराने होंगे।

नीट के विवादित सवाल की जांच के आदेश...उधर, संसद में हंगामा

लोकसभा में नीट पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच बहस, कांग्रेस नेता बोले

देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड

नई दिल्ली(ईएमएस)। नीट मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में फिजिक्स के 2 सही ऑप्शन वाले सवाल नंबर 19 की पड़ताल का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 सही ऑप्शन देने से 44 स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिले और 4.2 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान हुआ है। इस पर आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की राय लें। कोर्ट ने आदेश दिया कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर 2 जवाबों वाले सवाल की जांच के लिए एक 3 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। एक्सपर्ट टीम उनमें से एक सही ऑप्शन चुनकर मंगलवारको 12 बजे तक रजिस्ट्रार को अपनी राय भेजें। उधर, संसद के मानसून के पहले दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा- सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है।

प्रधान ने कहा कि 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार के लिए 3 बिल लाए। उनमें से एक अनियमितता रोकने के लिए था। उसे किसके दबाव में वापस लिया गया। क्या यह निजी मेडिकल कॉलेजों के दबाव के कारण था? और वे (राहुल गांधी) हमसे सवाल पूछ रहे हैं।

संसद के मानूसन सत्र में नीट पेपर लीक मुद्द को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक में नए रिकॉर्ड बना रही है। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी में हुए पेपर लीक की सूची है। संसद में अखिलेश यादव ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में छात्र विरोध कर रहे हैं। जांच में खुलासे हो रहे हैं। लगातार गिरफ्तारियां की जा रहीं हैं। मेरा कहना है कि अगर यही शिक्षा मंत्री रहे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम सार्वजनिक किया गया है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास सूची है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कितने पेपर लीक हुए? उन्होंने कहा कि एनटीए ने 240 से ज्यादा परीक्षाएं कराईं। इनमें पांच करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश के लिए एकल परीक्षा कराने के लिए कहा था। पहले नीट परीक्षा सीबीएसई कराता था। अब यह नीट कराता है।

कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने कहा कि सात साल में 17 बार पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि 24 लाख परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी सरकार ले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सात बार पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही है। एक और सांसद प्रेमचंदन ने कहा कि नीट भ्रष्टाचार परीक्षा के लिए शुरू हुए पंजीकरण से ही चालू हो गया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए संसदीय जांच समिति बनाने की मांग की।

लोकसभा में सरकार ने 2012 की रिपोर्ट का हवाला देकर खारिज की मांग ,बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा

पटना (ईएमएस)। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। केंद्र ने साफ किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से सोमवार को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जे के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।

बिहार की मांग के बाद केंद्र की यूपीए सरकार ने 2012 में इसके अध्ययन के लिए मंत्रियों के ग्रुप का भी गठन किया था। इसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। इसी को आधार बनाकर केंद्र ने एक बार फिर से बिहार सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बीते कुछ सालों से बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की मांग लगातार उठती रही है। बिहार में एक बार फिर यह मांग जोर पकड़ रही है।

दूसरे राज्यों से भी उठ रही मांग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के मुताबिक, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रावधान है। इस समय देश में कुल 29 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं। इनमें से 11 राज्य ऐसे हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। वहीं, अब भी बिहार, आंध्रप्रदेश, ओडिशा समेत पांच राज्य ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेट का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए पांच पैमाने तय किए गए हैं। इनमें राज्य में पहाड़ी इलाके और दुर्गम क्षेत्र ज्यादा हों। कम आबादी वाले राज्य या जनजातीय समुदाय का ज्यादा होना। इंटरनेशनल बार्डर वाले राज्य, इसकी सरहदें पड़ोसी देशों से लगती हों। आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़े राज्य। राज्य के पास इनकम का बड़ा स्त्रोत ना होना।

संघ से हटा प्रतिबंध, मायावती ने कहा.....तल्खी दूर करने के लिए

लखनऊ (ईएमएस)। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे है।

मायावती ने मामले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाकर पोस्ट में कहा, कि सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केन्द्र का निर्णय देशहित से परे और राजनीति से प्रेरित संघ तुष्टीकरण का निर्णय है ताकि सरकारी नीतियों व इनके (भाजपा सरकार) अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो।

मायावती ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जनकल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे संघ की गतिविधियां राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। मायावती ने निर्णय को अनुचित बताकर तुरंत वापस लेने की मांग की है। इसके पहले रविवार को, कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 9 जुलाई को जारी एक कार्यालय ज्ञापन साझा किया, जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित है। आदेश में कहा गया है, ''उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए।

आदेश की तस्वीर के साथ कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध को हटाया गया। इसके बाद भी आरएसएस ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि 4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और संघ के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। 9 जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था।

लगातार सातवां बजट पेश कर इतिहास रचेंगी निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली (ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं। इस तरह वह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। हालांकि, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी देसाई के पास ही है। सीतारमण अगले महीने 65 वर्ष की हो जाएंगी। उन्हें 2019 में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी। तब से सीतारमण ने इस साल फरवरी में एक अंतरिम सहित लगातार छह बजट पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल, 2024 से मार्च, 2025) का पूर्ण बजट उनका लगातार सातवां बजट होगा। वह देसाई के रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगी, जिन्होंने 1959 से 1964 के बीच लगातार पांच पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत में बजट पेश करने से जुड़े कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट 26 नवंबर, 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर कुल 10 बजट पेश किए हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नौ मौकों पर बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आठ बजट पेश किए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश किया, जब वह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे।

तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे किसान,15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च

नई दिल्ली (ईएमएस)। तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ किसान अब दिल्ली की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इसका ऐलान किया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसानों की ओर से देशभर में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की गई है। किसानों से संघु और शंभु समेत दिल्ली के लगते बॉर्डर पर पहुंचने की अपील की गई है। फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च के साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों की कॉपी को भी जलाया जाएगा।

किसान संगठनों ने फैसला किया है कि 1 अगस्त को वह मोदी सरकार की अर्थी जलाएंगे। इस दौरान एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने रणनीति बनाई है कि 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। इस दौरान नए क्रिमिनल लॉ की कॉपी भी जलाई जाएगी। देशभर के किसानों से सरकार की नीतियों का विरोध करने की अपील की गई है। शंभू बॉर्डर पर किसान महीनों का राशन लेकर पहुंचने लगे हैं।

31 अगस्त तक किसानों से शंभु बॉर्डर पहुंचने की अपील

किसान लंबे समय से शंभु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 31 अगस्त को इस धरने को 200 दिन पूरे हो जाएंगे। किसान संगठनों ने इस दिन सभी किसानों से अपील की है कि वो बॉर्डर पर पहुंचे।वहीं, हरियाणा में 15 सितंबर को जिंद में और 22 सितंबर को हरियाणा के ही पीपली में किसानों की रैली आयोजित होने वाली है।किसानों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को बेल देने की भी निंदा की। आशीष पर लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है।किसानों ने कहा कि बॉर्डर खुलते ही ट्रैक्टर में सामान भरकर हम दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का फैसला रोका, कहा- दुकानदारों को नाम बताने के लिए मजबूर न करें

नई दिल्ली(ईएमएस)। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों की पहचान के जरिए उनका आर्थिक बहि ष्कार किया जा रहा है। यह चिंताजनक है।

भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। होटल चलाने वालों को भोजन के प्रकार यानी वह शाकाहारी है या मांसाहारी की जानकारी देनी होगी। लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

ये दुकानदारों के लिए हैं आर्थिक मौत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्वैच्छिक है और ये अनिवार्य नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने केस इसको लागू किया है। इसको देखें वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दे गई कि अगर नहीं करते तो करवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये विक्रेताओं के लिए आर्थिक मौत की तरह है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है, जिस पर वकील ने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि यह जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ जाए। इसके तीन आयाम हैं - सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता और - तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये बात जस्टिस एसवीएन भट्टी ने कही जब सिंघवी ने कि ये पहचान का बहिष्कार है, आर्थिक बहिष्कार है।

यूपी के बाद उज्जैन और उत्तराखंड में आदेश जारी हुए

पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने निर्देश जारी किया था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी होटल-ढाबे और रेहड़ी संचालक मोटे-मोटे अक्षरों में अपना नाम और मोबाइल नंबर का बोर्ड लगाएंगे। जिससे ताकि कांवड़ियों को सामान खरीदते वक्त कोई कन्फ्यूजन न रहे। इसके बाद 19 जुलाई को यही आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया।

उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने भी अपने यहां यही आदेश जारी कर दिए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में भी 20 जुलाई को पुलिस ने सभी दुकानों पर पहचान लिखने के लिए कहा है। यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांवड़ यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूरी कर दिया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर दुकान खोलते हैं। उज्जैन में नगर निगम यह आदेश एक साल पहले ही दे चुका था। हालांकि, इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा था कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सख्ती से अमल करवाएंगे।

डिप्टी सीएम ने मांगा सीएम योगी के विभाग से कर्मचारियों के आरक्षण का ब्यौरा

-यूपी में अंदरूनी खींचतान के बीच केशव प्रसाद मौर्य का पत्र बना चर्चा का विषय

लखनऊ,(ईएमएस)। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विभाग को पत्र लिखा है जिसमें नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। इस पत्र में केशव मौर्य ने कहा है कि वह इस मुद्दे को विधान परिषद में भी उठा चुके हैं।

सीएम योगी के नियुक्ति और कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। पत्र में डिप्टी सीएम मौर्य ने लिखा कि-मैंने 11 अगस्त 2023 में इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया था और अधिकारियों से जानकारी मांगी थी। 16 अगस्त 2023 को उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन जानकारी नहीं मिलने से एक बार फिर पत्र लिखा और अधिकारियों को आदेशित किया था कि शासनादेश के मुताबिक समस्त विभागों को सूचीवार एकत्र करके, संकलित कर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन के बीच अंदरूनी खींचतान के बीच डिप्टी सीएम मौर्य का यह पत्र चर्चा में आ गया। हाल ही में संगठन और सरकार के बीच मतभेद सामने आए थे। उसके बाद केशव मौर्य को दिल्ली बुलाया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात की थी। इस बैठक में संगठन और सरकार के बीच तनाव को कम करने पर चर्चा हुई थी। नड्डा ने कहा था कि ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचे।

यूपी कार्यसमिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जो आपका दर्द है, वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव मौर्य ने आगे कहा था कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। डिप्टी सीएम के बस बयान के बाद यूपी की सियासत चर्चा के केंद्र में आ गई थी जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गरम हो गया था। विपक्ष ने भी इस खींचतान पर तंज कसे थे।

सुप्रीम कोर्ट में शंभू बार्डर खोलने के मामले की सुनवाई टली

नई दिल्ली (ईएमएस)। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बार्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के नीट मामले में व्यस्त होने के कारण सोमवार को सुनवाई टल गई.

हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.

हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, कोर्ट इस पर तैयार हो गया था. जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था कि वो इस मामले पर 22 जुलाई को सुनवाई करेंगे.

खालिस्तानियों ने दी संसद भवन और लाल किला उड़ाने की धमकी

-सांसद वी शिवदासन को आया फोन, राज्यसभ41 के सभापति को लिखा पत्र

नई दिल्ली,(ईएमएस)। केरल से राज्यसभा सांसद वी शिवदासन को धमकी भरा फोन आया है। सांसद के मुताबिक उन्हें फोन पर धमकी दी गई कि संसद भवन और लाल किले को बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह धमकी भरा फोन कॉल खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (एसजेएफ) के नाम किया गया था। इस बात को लेकर सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें एसजेएफ के नाम पर फोन कॉल आया था। वी शिवदासन केरल से सीपीआई (एम) के सांसद हैं। धमकी देने वाले ने गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम लिया है।

राज्यसभा सभापति को पत्र में सांसद वी शिवदासन ने लिखा है कि मुझे सिख फॉर जस्टिस (एसजेएफ) के नाम पर एक धमकी भरा फोन आया था। उन्होंने लिखा है कि यह धमकी 21 जुलाई को रात 11 बजकर 30 मिनट पर मिली। सांसद ने बताया कि जिस वक्त उनके पास फोन आया वह आईजीआई एयरपोर्ट लाउंस में थे और उनके साथ सांसद ए रहीम थी मौजूद

मानसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी ,जितनी लड़ाई लडऩी थी, लड़ ली; अब सिर्फ देश के लिए काम करें

नई दिल्ली (ईएमएस)। संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है। इस पावन दिन पर एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। मैं सावन के पहले सोमवार पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। आज पूरे देश की नजर इस पर है। देश बहुत बरीकी से देख रहा है कि संसद का ये सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे और हमारे सभी साथियों के लिए भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखें।

अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट

उन्होंने कहा कि कल हम जो बजट पेश करेंगे, वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें पांच साल का जो अवसर मिला है, ये बजट हमारे उन पांच साल की दिशा तय करेगा। ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढऩे वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8 प्रतिशत ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत को लेकर सकारात्मकता बढ़ रही है, निवेश चरम पर है, ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का अहम पड़ाव है।

सभी सांसदों से किया खास अनुरोध

प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहता हूं कि गत जनवरी से लेकर अब तक हमें जितना संघर्ष करना था। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया। किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं सभी दलों से कहना चाहता हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए खुद को समर्पित करें और संसद के इस गरिमामय मंच का अगले 4.5 साल तक उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनावी साल में आप कोई भी खेल खेल लें, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, देश के लिए है। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृध्द करें, कितने ही विरुद्ध विचार होंगे। देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है बल्कि देश को प्रगति की विचारधारा से आगे बढ़ाना है। हम लोकतंत्र के इस मंदिर से भारत की सामान्य मानविकी की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे।

जन हितैषी

नए विवाद को जन्म देगा केंद्र का आदेश

शासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में हो सकेंगे शामिल

9 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों के सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। यह आदेश भारत सरकार के पर्सनल एवं पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन एवं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश पर डिप्टी सेक्रेटरी के हस्ताक्षर हैं। इस आदेश पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य शामिल होने की बात सामने आई थी। तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा ही प्रतिबंध 1966 में भी लगाया गया था। 1970 और अक्टूबर 1980 में भी केंद्र सरकार ने संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था। जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराया गया था। उस समय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अन्य पांच संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर प्रतिबंध लगाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं और संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर प्रतिबंध था। 58 साल से यह प्रतिबंध लगा हुआ था। इस प्रतिबंध को मोदी सरकार ने 9 जुलाई 2024 को हटा लिया है। इस आदेश के बाद अब कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी संघ के किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। अब कोई रोक-टोक नहीं होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वैचारिक संगठन है। विचारधारा के प्रचार प्रसार को लेकर वह अपनी सोच के अनुसार विचारधारा को बढ़ावा देने का काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 80 से ज्यादा अनुवांशिक संगठन हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संविधान के अनुसार नियम और कानून के तहत काम करते हैं। जहां विचारधारा के स्थान पर, मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का काम सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को करना होता है। हाल ही में जिस तरह से कई न्यायपालिका के जजों और बड़े-बड़े अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपनी निष्ठा जताते हुए सार्वजनिक रूप से इज़हार किया है। वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। ऐसी स्थिति में विचारधारा से संचालित होने वाले अन्य धार्मिक संगठन भी इसी तरह की मांग कर सकते हैं। जो भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत होगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों में जाने की छूट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल गई है। अन्य धर्मों अथवा विचारधारा से संचालित इस तरह के संगठन, वह भी केंद्र सरकार से इसी तरह की छूट मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की क्या भूमिका होगी। इसे समझना भी बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों द्वारा किस तरह से नाथूराम गोडसे को अपना आराध्य माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साहित्य में गांधी जी की भूमिका तथा भारतीय संविधान के बारे में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वह संवैधानिक प्रावधान के विपरीत हैं। गांधी जी की हत्या को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठन समय-समय पर सही ठहराने का प्रयास करते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय संविधान के विपरीत एक अलग विचारधारा का पोषण करता है। ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें शामिल होने देने से, भविष्य में कई तरह की परेशानियां और विवादों का सामना केंद्र एवं राज्य सरकारों को करना पड़ सकता है। पिछले 58 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों और शाखाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उसके बाद भी व्यक्तिगत तौर पर निजी आस्था को ध्यान में रखते हुए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी समय-समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। उस पर इसलिए कोई विवाद नहीं उठा, वह निजी हैसियत से कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से अधिकार पूर्वक शामिल हो सकेगा। इस आदेश पर राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की तीव्र प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार के इस आदेश ने एक नए विवाद को जन्म दिया है। इस आदेश की जानकारी लगते ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी है। महात्मा गांधी की हत्या के लिए कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार मानती है। न्यायालय से भले सबूत और तकनीकी के अभाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न्यायालय द्वारा निर्दोष बताया गया। नाथूराम गोडसे को आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुवांशिक संगठन गांधी जी की हत्या को सही कदम बताते हैं। संघ के इतिहास में आज भी नाथूराम गोडसे को शहीद का दर्जा है। भारत ने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। महात्मा गांधी की हत्या के 75 वर्ष बाद और पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारत में गोडसेवाद एक बार फिर लौट कर सामने आया है, उसके बाद चिंता होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद डेढ़ दशक तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सारी गतिविधियां बंद थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगातार प्रयास करने और महात्मा गांधी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं होने तथा 1962 के चीन भारत युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्रीयता के आधार पर प्रतिबंध समाप्त कराया था। एक बार फिर सामाजिक गतिविधियों में संघ सक्रिय हुआ था। 2014 के बाद से जिस तरह से गोडसे को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। नाथूराम गोडसे की मूर्तियां और मंदिर तैयार किये जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था तैयार की जा रही है। पिछले वर्षों में शासकीय अधिकारियों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी निष्ठा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जोड़ी है। उसके बाद इस आदेश पर तीव्र प्रतिक्रिया होना तय है। जिस तरह के हालात देश में बने हुए हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर देश में विभिन्न समुदायों को आपस में बांटा जा रहा है। ऐसे समय पर भारत सरकार द्वारा संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने की छूट देने से, सरकार ने एक नये विवाद को जन्म दिया है। इस आदेश पर तीव्र प्रक्रिया होना तय है।

देश में बढ़ रही कुतर्क की राजनीति

राजनीति में सकारात्मक दिशा के अभाव में देश को जो नुकसान उठाना पड़ता है, वह भले ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे, लेकिन उससे समाज पर प्रभाव अवश्य ही होता है। अगर यह प्रभाव नकारात्मक चिंतन की धारा के प्रवाह को गति देने वाला होगा तो देश को भी अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ता है। वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, उसे भटकाव पैदा करने वाली राजनीति कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, जो विषय राजनीति के नहीं होने चाहिए, उनको भी राजनीतिक दल राजनीति के दल दल में ले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के किसी भी निर्णय का अपने हिसाब से परिभाषित करना राजनीति का प्रिय विषय बनता जा रहा है। इससे प्रायः मूल विषय बहुत पीछे छूट जाता है और बहस कहीं और चली जाती है।

आज के राजनीतिक वातावरण का अध्ययन किया जाए तो यही परिलक्षित होता है कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई भी किसी दूसरे की बात को ऐसे तर्क देकर उसका प्रक्षालन करते हैं, जैसे केवल उनकी ही बात सही है और बाकी सब गलत बयानी कर रहे हैं। हालांकि यह बात सही है कि कमी सभी जगह होती है, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होते हैं, आज इन अच्छे कामों की चर्चा कहीं भी नहीं हो रही है। सब एक दूसरे की गलतियां निकालने में ही राजनीति का मुख्य उद्देश्य बनता जा रहा है। यह राजनीति की सकारात्मक दिशा तो कतई नहीं मानी जा सकती। प्रछ्छ्ष्ठ इसे नकारात्मक राजनीति अवश्य कहा जा सकता है। ऐसी राजनीति आम जनता में भटकाव पैदा करती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है, क्योंकि जो जनता सरकार के विरोध का विचार रखती है, वह विपक्ष की हर बात को सही मानकर ही व्यवहार करेगी और जो विपक्ष की बातों पर भरोसा नहीं करती, उसे सत्ता पक्ष की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वास्तव में ऐसी राजनीति के बजाय देश हित की राजनीति करने की ओर सभी दलों को आगे आना चाहिए। लेकिन आज के वातावरण में ऐसा होना संभव नहीं लगता। क्या यह सही नहीं है कि देश में भाजपा के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, लेकिन विपक्ष इस बहुमत वाली सरकार को पराजित सरकार कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि यह मानने में कोई अतिरेक नहीं है कि विपक्ष पहले से मजबूत हुआ है, लेकिन वह विपक्ष में ही है। इसको भी खुले मन से स्वीकार करने की मानसिकता बनानी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि राजनीति देश को सही दिशा में ले जाने की हो रही है।

आजकल समाचार के विभिन्न माध्यमों पर सामयिक विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन इन चर्चाओं में सभी तरफ से पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्तियों को ही शामिल करने का चलन हो गया है। दूसरे की बात को नकारना ही इन चर्चाओं का एकमेव सिद्धांत बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, कोई एंकर अपनी ओर से भारत के चिंतन पर आधारित कोई तथ्य रखता है तो उस एंकर को भी किसी राजनीतिक दल का समर्थक बताने में कोताही नहीं की जाती। हो सकता है कि कोई पत्रकार विचारधारा से किसी राजनीतिक दल की बात को सही ठहराने की वकालत कर रहा हो। क्योंकि आज के समय में अधिकांश पत्रकार और समाचार पत्र किसी न किसी राजनीतिक दल का खुल कर समर्थन करता है तो कोई विरोध की शैली ही अपनाता है। ऐसी पत्रकारिता भी ठीक नहीं कही जा सकती, लेकिन कई समाचार चैनल ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष तरीके से बहस कराते हैं। यह एंकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही सवाल करते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं की ओर से एंकर को सवालों के घेरे में खड़े करना ठीक नहीं कहा जा सकता। आजकल जो डिबेट चल रही हैं, उनमें विपक्ष की ओर से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे उन्होंने भाजपा को हरा दिया है। इसके लिए अगर कोई एंकर विजयी सांसदों की संख्या बताता है तो तर्क वितर्क प्रारंभ हो जाता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ज़ब यह तर्क वितर्क से आगे बढ़कर कुतर्क की शैली में आ जाता है तो विवाद होने लगता है। राजनेताओं को राजनीतिक लड़ाई केवल दलीय आधार पर करना चाहिए, लेकिन यहां पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने तरकस से तीर निकालने का प्रयास किया जाता है। अगर भाजपा का कोई प्रवक्ता तीसरी बार सरकार बनाने की बात को लोकतंत्र की विजय निरुपित करता है तो इसमें गलत क्या है। इसे विपक्ष को खुले मन से स्वीकार करने में हिचक क्यों हो रही है। एक कहावत है कि सच बहुत कड़वा होता है, जिसने सच को स्वीकार करना सीख लिया, वह कुतर्क करने की चेष्टा नहीं कर सकता।

लोकतंत्र क्या है? इसकी परिभाषा या तो राजनेता जानते नहीं हैं या फिर जानते हुए भी नहीं जानने का नाटक करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा ''जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। राजनेता तो मात्र जनता के प्रतिनिधि ही हैं। लेकिन वर्तमान में राजनेता जनता से ऊपर मानने की ओर प्रवृत हो चुके हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत की जनता ने लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीट भाजपा को दी हैं। इसे सीधे अर्थों में प्रदर्शित किया जाए तो यही कहना उचित होगा कि भाजपा ही जनता की पहली पसंद है। उसे जनता ने 240 सीट दी है। बाकी का कोई भी दल तीन अंकों की संख्या तक भी नहीं पहुँच सका है। ऐसे में क्या यह नहीं कहा जाना चाहिए कि मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी विपक्ष सरकार बनाने में सफल नहीं हो सका। इसे हार ही कहा जाएगा, लेकिन विपक्ष इसी हार को ऐसे प्रचारित कर रहा है, जैसे यह उसकी बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस ने भले ही अपनी स्थिति में सुधार करते हुए प्रदर्शन किया हो, लेकिन इसे बड़ी जीत नहीं कहा जा सकता। सत्य यह भी है कि कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है, वह उसके अपने परिश्रम का परिणाम नहीं है। उत्तरप्रदेश में अगर सपा का समर्थन नहीं होता तो कांग्रेस किस स्थिति में होती, यह अनुमान लगाया जा सकता है। यहां एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, कांग्रेस राष्ट्रीय दल होने के बाद भी सपा से बहुत पीछे है। इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। यही लोकतंत्र की जीत है। तर्क वितर्क और कुतर्क करने की राजनीति से भ्रम की स्थिति बनती है। इस प्रकार की राजनीति का कोई ठोस आधार नहीं होता। (लेखक- सुरेश हिंदुस्तानी/ ईएमएस)

फिर आतंकी हमलें, सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाये

लगातार जम्मू-कश्मीर में बढ़ रही आतंकी घटनाएं चिन्ता का कारण बन रही है। डोडा जिले में एक आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के चार जवानों और जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी का बलिदान अब यही दर्शा रहा है कि शांति एवं अमन की ओर लौटा जम्मू-कश्मीर एक बार फिर आतंकवादी आघातकारी घटनाओं की भेंट चढ़ रहा है, इन घटनाओं का माकुल जबाव नहीं दिया गया तो यह घाटी एक बार फिर खूनी घाटी बन जायेगी। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कठुआ में एक सैन्य अफसर सहित पांच जवान आतंकियों का निशाना बन गए थे। इसके पहले भी जम्मू संभाग में ही सेना के कई जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। ये बहुत चिंतित करने वाले त्रासद एवं घिनौने घटनाक्रम हैं कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हाल की कुछ घटनाओं से तो यह भी लगता है कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। एक ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, तब आतंकियों का सक्रिय होना और सफलतापूर्वक अपने मनसूबों को कामयाब करना गंभीर चिंता का विषय है।

ज्यादा चिन्ताजनक यह है कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी सफल हो रहे हैं। सरकार को उन खूनी हाथों को खोजना होगा अन्यथा खूनी हाथों में फिर खुजली आने लगेगी। हमें इस काम में पूरी शक्ति और कौशल लगाना होगा। आदमखोरों की मांद तक जाना होगा। अन्यथा हमारी खोजी एजेंसियों एवं सेना की काबिलीयत पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा कि कोई दो-चार व्यक्ति कभी भी पूरे प्रांत की शांति और जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं, हमारी संवेदनाओं को झकझोर सकते हैं। संवेदनाओं एवं भावनाओं को झकझोर भी रहे हैं, जब आतंकवादी हमलों में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटे घर की डयोढ़ी पर आते हैं तब कारुणिक माहौल को देखकर दिल दहल उठता है क्योंकि देश के लिए अपना सर्वोच्च लुटा देने वाला जवान किसी का बेटा, किसी का पति और किसी का पिता होता है। हर आंख में आंसू होते हैं। किसी की गोद, किसी की मांग सूनी हो जाती है। देशवासी सोचने को विवश हैं कि वे शोक संतप्त परिवार के साथ करुणा और पीड़ा को कैसे बांटें।

डोडा वारदात की जिम्मेदारी लेने वाले 'कश्मीर टाइगर्स' जैसे आतंकी संगठनों की ताजा बौखलाहट की एक बड़ी वजह जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली को लेकर बढ़ी सरगर्मी है। राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए अगले चंद महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में, आतंकियों की बेचैनी समझी जा सकती है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में घाटी में लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े और दशकों पुराना रिकॉर्ड टूटा, अगर विधानसभा चुनाव में लोगों का उत्साह और बढ़ा, तो जिन 'स्लीपर सेल्स' की बदौलत वे दहशत का अपना पूरा कारोबार चलाते हैं, वे भी मुख्यधारा के प्रति आकर्षित होकर, उनके खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने घाटी के बजाय जम्मू संभाग में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित किया जा सके और सीमा पार के आकाओं से मदद हासिल करने का सिलसिला जारी रहे।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान से पाकिस्तान बौखलाया है। इसी का परिणाम है लगातार हो रहे आतंकी हमलें। इन हमलों ने आंतरिक सुरक्षा के लिये नये सिरे से चुनौती पैदा की है। जम्मू में रियासी, कठुआ और डोडा के आतंकी हमले चिन्ता का बड़ा कारण बने है। जम्मू-कश्मीर का माहौल सुधरने के बाद वहां के बाजार, पर्यटक स्थल गुलजार हुए हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। इसलिए देशद्रोही नहीं चाहते कि कश्मीर में शांति आए और वहां पर निर्वाचित सरकार काम करे। केन्द्र में गठबंधन वाली मोदी सरकार के सामने यह एक बड़ी चुनौती है। क्या इन आतंकी घटनाओं को केन्द्र सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया है? जो सरकार पाकिस्तान में घूस कर बदला ले सकती है, वह सरकार अब तक शांत क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाने की जरूरत है। आतंकी जिस तरह अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों को कहीं अधिक क्षति पहुंचाने में समर्थ दिखने लगे हैं, वह किसी बड़ी साजिश का संकेत है। एक ओर सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को नए सिरे से सबक भी सिखाना होगा। यह इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों में बलिदान होने वाले सैनिकों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी है।

पाकिस्तान सत्ता प्रतिष्ठानों की मदद से यह आतंक का खेल फिर शुरू कर रहा है। कहीं न कहीं दिल्ली में बनी गठबंधन सरकार को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पाक पोषित आतंकवादी जम्मू-कश्मीर में शांति एवं अमन को कायम नहीं रहने देंगे। एक आंकड़े के अनुसार पिछले तीन वर्ष में करीब 50 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आतंक को करारा जवाब केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए, जब एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को बलिदान देना पड़े। वास्तव में हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। डोडा की घटना के बाद यह जो कहा जा रहा है कि सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा, उसे न केवल पूरा करके दिखाया जाना चाहिए, बल्कि आतंकियों, उनके आकाओं और उन्हें सहयोग-समर्थन देने वालों पर ऐसा करारा प्रहार किया जाना चाहिए, जिससे वे अपनी हरकतों से हमेशा के लिए बाज आएं। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा हो, लेकिन वह जम्मू कश्मीर में पहले की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। उसकी घरेलू व विदेश नीति 'कश्मीर' पर ही आधारित है। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि चीन उसे उकसाने में लगा हुआ होगा, इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा।

केन्द्र सरकार ने कश्मीर में विकास कार्यों को तीव्रता से साकार किया है, न केवल विकास की बहुआयामी योजनाएं वहां चल रही है, बल्कि पिछले 10 सालों में कश्मीर में आतंकमुक्त करने में भी बड़ी सफलता मिली है। बीते साढ़े तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। लेकिन वहां विकास एवं शांति स्थापना का ही परिणाम रहा कि चुनाव में लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया। बढ़ती आतंकी घटनाओं पर गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुरक्षा बल आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देगा लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा बलों को आतंकियों के प्रति अपनी रणनीति बदलनी होगी और आतंकी जिन बिलों में छिपे होंगे उन्हें वहां से निकालकर ढेर करना होगा। आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने की तैयारी करनी होगी और साथ ही आतंकियों के मददगारों की भी पहचान करनी होगी, तभी आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया जा सकता है।

पुलिस के आला अधिकारी यदि यह कह रहे हैं कि घाटी के नागरिक समाज में पाकिस्तानी 'घुसपैठ' को बढ़ावा देने में कतिपय राजनीतिक दलों का रुख भी जिम्मेदार रहा है, तो क्या यह आधारहीन है? इसका मुकाबला हर स्तर पर हम एक होकर और सजग रहकर ही कर सकते हैं। यह भी तय है कि बिना किसी की गद्दारी के ऐसा संभव नहीं होता है। ताजा आतंकी हमलों के विकराल रूप कई संकेत दे रहे हैं, उसको समझना है। कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसका उत्तर देना है। यह पाकिस्तान का बड़ा षड़यंत्र है इसलिए इसका फैलाव भी बड़ा हो सकता है। ये घटनाएं चिल्ला-चिल्ला कर कह रही हैं हमारी खोजी एजेन्सियों से, हमारी सुरक्षा व्यवस्था से कि वक्त आ गया है अब जिम्मेदारी से, सख्ती से और ईमानदारी से जम्मू-कश्मीर को संभालें। (लेखक- ललित गर्ग / ईएमएस)

अच्छे वैज्ञानिक अनुसन्धान हेतु वैज्ञानिकों पर भरोसा आवश्यक

विज्ञान पर तो दुनिया विश्वास करती है एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया भर के लोगों ने वैज्ञानिकों पर भरोसा व्यक्त किया है, लेकिन वे अनुसंधान में सरकारों के हस्तक्षेप को लेकर चिंतित भी हैं। यह निष्कर्ष वैश्विक संचार संस्थान एडेलमैन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट ट्रस्ट बैरोमीटर का है जिसके लिए मेक्सिको से लेकर जापान तक 28 देशों के 32,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों सम्बंधित सही जानकारी प्रदान करने के लिए वैज्ञानिकों पर विश्वास जताया है। इतने ही प्रतिशत लोगों ने चाहा है कि वैज्ञानिक इन नवाचारों को पेश करने में स्वयं आगे आएं। इसके विपरीत, सही जानकारी देने के संदर्भ में लोगों ने पत्रकारों और सरकारी नेताओं पर क्रमशः 47 प्रतिशत और 45 प्रतिशत ही भरोसा जताया है। हालांकि, अध्ययन में 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने देश में विज्ञान के राजनीतिकरण की बात कही है, जो राजनेताओं के हस्तक्षेप की ओर इशारा करता है। विश्व स्तर पर 59 प्रतिशत का मानना है कि सरकारें और अनुसंधान वित्तपोषक एजेंसियां वैज्ञानिक प्रयासों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। ये आंकड़े भारत में 70 प्रतिशत और चीन में 75 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 60 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सरकारों में उभरते नवाचारों के नियमन की क्षमता का अभाव है। यह भरोसा वैज्ञानिकों के लिए एक अवसर के साथ चुनौती भी है। इस विश्वास के दम पर वैज्ञानिक प्रयास कर सकते हैं कि सरकारी नीतियां प्रमाण-आधारित बनें। इसके साथ ही वे सरकारी हस्तक्षेप और नियामक शक्तियों पर लोगों के अविश्वास सम्बंधी चिंताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। सवाल यह उठता है कि सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए, नीतियों की दिशा सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक सरकारों के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं? कई विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण बताते हैं जो कोविड-19 महामारी और कृत्रिम बुद्धि के उदय जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और नवाचार पर वैश्विक फोकस के साथ मेल खाती है। हालिया समय में दुनिया भर की सरकारें क्लस्टरिंग विश्वविद्यालयों से लेकर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और नवीन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करने की विभिन्न रणनीतियों की तलाश कर रही हैं। एक हालिया प्रस्ताव में चिकित्सा विज्ञान में एआई की बड़ी भूमिका की वकालत की गई है लेकिन नियामक सुधारों को भी आवश्यक बताया है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में सामाजिक विज्ञान एक ऐसे उपकरण के रूप में उभरा है जिसका उपयोग नहीं किया गया है। यूके एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज़ की एक रिपोर्ट में डैटा वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, नैतिकताविदों, कानूनी विद्वानों और समाजशास्त्रियों की विशेषज्ञता की चर्चा करते हुए नीति निर्माण में सामाजिक विज्ञान को जोड़ने पर ज़ोर दिया गया है। इन क्षेत्रों के पेशेवर लोग नई प्रौद्योगिकियों, आर्थिक मॉडलों और नियामक ढांचे की ताकत और सीमाओं का आकलन कर सकते हैं और उनमें निहित अनिश्चितताओं को भी संबोधित कर सकते हैं। यदि लोगों को लगता है कि विज्ञान का राजनीतिकरण हो चुका है और सरकारें बहुत अधिक हस्तक्षेप कर रही हैं, तो यह सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी समस्या है क्योंकि इससे लोगों के इस विश्वास में कमी आ सकती है कि सरकारें इन नवाचारों के लाभ उन तक पहुंचाएंगी और संभावित नुकसानों से बचाएंगी। ऐसे में वैज्ञानिकों को नवाचार के बारे में विश्वसनीय स्रोत बनने के अवसर है। (लेखक- संजय गोस्वामी / ईएमएस)

शब्द पहेली - 8076

बाएँ से दाएँ

1. अँगरखा-4
3. मान-सम्मान, इज्जत-3
5. शुभाशीर्वाद, नियामत-4
8. केश-2
10. कसम, प्रतिज्ञा, वचन-2
11. बुरी आदत-2
13. मगरमच्छ-3
15. परिणाम-3
16. माँड़ी, स्टार्च-3
17. अक्षर (उर्दू-3)
19. रोम, केश-2
20. अधिकार, आरोप-2
21. सतह, स्तर, पटल-2
23. लूटपाट, डाका-4
25. सभ्यीकरण, विवेक-3
26. एक प्रसिद्ध कवि-4

ऊपर से नीचे

1. अनोखा, विचित्र, विलक्षण-3
2. नया, नवीन-2
3. इज्जत-2
4. कपोल-4
6. गमन, प्रेषित-3
7. पिता के पिता-2
9. चुनौती-4
13. गंदगी का ढ़ेर-3
14. असावधानी-4
17. जेल, कालकोठरी-4
18. शोर, ध्वनि, कंपन्न-3
20. ताप, शवदाह-2
22. यज्ञ, आहुति दान-3
23. रहस्य-2
24. जल, पानी-3

शब्द पहेली -8075 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से संन्यास ले लेंगे श्रीजेश

पेरिस (ईएमएस)। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कहा कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद खेल से संन्यास ले लेंगे। इस प्रकार ये श्रीजेश का अंतिम अंतरराट्रीय टूर्नामेंट होगा। अपने करियर में अब तक 328 मैच खेलने वाले श्रीजेश का यह चौथा ओलंपिक है। 36 साल के श्रीजेश ने कई अवसरों पर भारतीय टीम की कप्तानी भी की है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और विश्व कप के साथ ही 2021 में आयोजित हुए टोक्यो ओलंपिक में शानदार गोलकीपिंग की थी। हॉकी इंडिया ने भी श्रीजेश को उनके शानदार करियर के लिए बधाई दी है।

हॉकी इंडिया ने उन्हें जीत के साथ विदायी देने के लिए 'विन इट फॉर श्रीजेश का अभियान शुरू किया है जो खिलाड़ियों को फिर से पोडियम पर खडे होने के लिए प्रेरित करेगा। श्रीजेश ने भारतीय टीम के लिए साल 2010 में पदार्पण किया था। वह 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम में भी शामिल रहे थे। वह 2018 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की संयुक्त विजेता टीम, भुवनेश्वर में 2019 एफआईएच पुरुष सीरीज फाइनल की स्वर्ण पदक विजेता टीम और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक विजेता टीम में भी शामिल थे।

उन्होंने भारत को एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2021-22 में तीसरे स्थान पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें साल 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 'वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार भी उन्हें मिला है। उन्हें साल 2021 और 2022 में लगातार दो बार एफआईएच 'गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। उन्होंने पिछले साल एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया था।

श्रीजेश ने कहा, 'मैं पेरिस में अपने आखिरी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा हूं, मुझे अपने करियर पर बहुत गर्व है और उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मेरी अब तक की यात्रा असाधारण रही है और और मैं अपने परिवार, टीम के साथियों, सभी कोच, प्रशंसकों और हॉकी इंडिया के प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी हूं।

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई को तटस्थ स्थल पर खेलने आमंत्रित कर सकता है पीसीबी

इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) अध्यक्ष मोहसिन नकवी अगले साल किसी तटस्थ स्थल पर भारतीय टीम को टी20आई सीरीज खेलने का आमंत्रण दे सकते हैं। माना जा रहा है कि पीसीबी प्रमुख चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोनों टीमों को खाली समय में खेलने के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) चैम्पयंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाक भेजने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पीसीबी अभी भी इस मामले में बीसीसीआई को मनाने का प्रयास कर रहा है।

पीसीबी ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के सभी मैच लाहौर में रखे गये हैं और भारतीय टीम पूरी सीरीज के दौरान एक ही होटल में रुकेगी। साथ ही कहा है कि एक शहर में होने से टीम को अच्छी सुरक्षा प्रदान करना आसान हो जाएगा। पीसीबी ने हाल ही में घोषणा की कि उसने लाहौर में गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम के बगल में जमीन खरीदी है। इसमें एक एक 5-सितारा होटल बनाया जाएगा। जिससे खिलाड़ियों को यहीं ठहराया जा सके।

पीसीबी ने होटल का निर्माण खुद करने की योजना बनाई है और अगले साल की शुरुआत तक निर्माण पूरा करने की योजना है। पीसीबी के अनुसार इस नये होटल से टीमों को दूर के होटलों में ठहरने की जरूरत नहीं रहेगी और सुरक्षा के लिए सड़क बंद होने की समस्या भी समाप्त खत्म हो जाएगी।

रुट ने विराट, स्मिथ और विलियम्सन को पीछे छोड़ा

मुम्बई (ईएमएस)। इंग्लैंड के जो रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक लगाने के साथ ही वर्तमान समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों (फैब फोर) की सूची में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। रुट अब टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने के मामले में भारत के विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के केन विलियम्सन से आगे निकल गये हैं। रूट ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 120 रन बनने के साथ ही विराट, स्मिथ और विलियम्सन को पीछे छोड़ा। रूट के नाम अब 142 टेस्ट मैच में 11940 रन हो गये हैं। अब उनसे आगे केवल वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज ब्रायन लारा हैं। लारा के नाम 131 टेस्ट में 11953 रन हैं।

रूट फैब फोर में एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 10 हजार से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। स्मिथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 109 टेस्ट मैच में 9685 रन बनाए हैं जबकि विराट के नाम 113 टेस्ट में 8848 रन हैं। वहीं विलियम्सन चौथे नंबर पर हैं। उनके नाम 8743 रन हैं।

रूट की नजरें अब कुमार संगकारा के 12400, एलिस्टेयर कुक के 12472 और राहुल द्रविड़ के 13288 टेस्ट रनों से आगे निकलना रहेगा।

नीरज अब ओलंपिक में भाग लेने पूरी तरह से फिट : कोच बार्टोनिट्ज

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के कोच जर्मनी के क्लॉस बार्टोनिट्ज ने कहा है कि अब वह पूरी तरह से ठीक हैं और ओलंपिक में भाग लेने के लिए तैयार हैं। बार्टोनिट्ज के अनुसार नीरज के जांघ की चोट अब पूरी तरह से ठीक हो गयी है और वह पूरी तरह से फिट हो गये हैं। बार्टोनिट्ज ने कहा कि अब सभी कुछ ठीक हो गया है और योजना के अनुसार चल रहा है। उन्होंने कहा, ''सब कुछ योजना के अनुसार है। अभी जांघ की चोट की कोई समस्या नहीं है, ऐसे में उम्मीद है कि ओलंपिक तक सभी अच्छा होगा।'' बार्टोनिट्ज पिछले पांच साल से नीरज के साथ हैं।

नीरज को मई माह में जांघ में कुछ दर्द महसूस हुआ था। तभी वह ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक से हट गये थे। इसी कारण वह सात जुलाई को पेरिस डायमंड लीग में भी नहीं खेले थे। ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा अगले माह छह अगस्त को क्वालीफिकेशन दौर से शुरू होगी जिससे अभी समय है। उन्होंने कहा कि नीरज टोक्यो ओलंपिक की तरह ही टूर्नामेंट की जगह पर ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और वह अपने 'ग्रोइन' पर दबाव कम करने के लिए अपनी 'ब्लॉकिंग' करने वाले पैर को मजबूती देने पर भी काम कर रहे हैं।

उन्होंने पदक की संभावनाओं को लेकर कहा, ''ओलंपिक में काफी कुछ दांव पर लगा होता है और काफी दबाव होता है जिससे कुछ भी हो सकता है। आंकड़ों के आधार पर पदक का अनुमान लगाना मुश्किल है।''

पेरिस ओलंपिक के लिए शामिल तीरंदाजी फिजियो पर उठे सवाल

विश्व चैंपियनशिप के दौरान कनाडाई किशोर खिलाड़ी ने लगाये थे आरोप

पेरिस (ईएमएस)। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के फिजियो अरविंद यादव को दल में शामिल करने पर विवाद उठ खड़े हुए हैं। अरविंद पर पिछले साल आयरलैंड में हुई युवा विश्व चैंपियनशिप के दौरान एक कनाडाई किशोर खिलाड़ी के साथ खराब व्यवहार के आरोप लगे थे। वहीं यादव ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही सवाल किया कि तब उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी। वहीं उनके विरोधियों का कहना है कि यादव का बचाव एएआई के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं। इसी कारण किसी भी शीर्ष प्रतियोगिता में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। वह रियो ओलंपिक में भी भारतीय दल में शामिल था।

इस बार भी वह तीन महीने पहले ही राष्ट्रीय शिविर से जुड़े पर उन्हें एक्रिडिटेशन मिल गया। एएआई चाहता तो उनकी जगह पर मुख्य कोच को दल में शामिल कर सकता था। वहीं इसको लेकर एएआई अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीरंदाज ही उन्हें सहयोगी स्टाफ का हिस्सा बनाना चाहते थे।

महिला एशिया कप में पाक ने नेपाल को 9 विकेट से हराया

कोलंबो (ईएमएस)। पाकिस्तान की टीम ने महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नेपाल को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नेपाल की टीम ने 6 विकेट पर 108 रन बनाये। वहीं पाक टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा और मुनीबा अली की शानदार पारी के बल पर ये मुकाबला जीत लिया। इससे पाक टीम के टूर्नामेंट में आगे जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। नेपाल के खिलाफ पाक टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। पाक टीम की कप्तान निदा डार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो सही साबित हुआ। फातिमा सना और सादिया इकबाल के अलावा सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। पाक की ओर से सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा और मुनीबा अली तेजी से बल्लेबाजी की।

जन हितैषी

पृष्ठ :3 दिनांकः 23-07-2024 मंगलवार अहमदाबाद

इधर बाइडन ने उम्मीदवारी छोड़ी, उधर खुशी से झूम उठे ओवामा, करने लगे जमकर तारीफ

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिका में राष्ट्रपति जो भी बनेगा वो बहुत खुश होगा और जश्न मनाएगा। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओवाम खुशी से झूम रहे हैं। उनकी खुशी का कारण है,जो बाइडन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। एक दिन पहले ही ओवामा ने बाइडन से मुलाकात की थी इसके बाद माना जा रहा था कि बाइडन उम्मीदवारी छोड़ देंगे। बराक ओबामा ने कहा कि जो बाइडन अमेरिका के सबसे अहम राष्ट्रपति है, साथ ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। आज एक बार फिर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वह सच्चे देशभक्त हैं। ओबामा को बतौर उपराष्ट्रपति चुनने के समय को याद करते हुए ओबामा ने कहा कि 16 साल पहले जब मैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तलाश कर रहा था तो मुझे जो बाइडन के जनसेवा के क्षेत्र में शानदार करियर के बारे में पता था। लेकिन मैं उनकी तारीफ उनके जुझारूपन और सहानुभूति वाले चरित्र और उस विचार के लिए करता है, जिसमें वो हर नागरिक को अहम मानते हैं।

जो बाइडन की उपलब्धियां गिनाते हुए ओबामा ने कहा कि देश के कोरोना महामारी को खत्म करने, लाखों नौकरियां पैदा करने, दवाइयों की कीमत कम करने, हथियार सुरक्षा से संबंधी कानून बनाने, देश के इतिहास में जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़ा निवेश करने और हर नागरिक के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में बाइडन ने शानदार काम किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने, नाटो को फिर से संगठित करने और यूक्रेन में रूस की आक्रामकता का जवाब देने में भी बाइडन की भूमिका काफी अहम रही।अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बाइडन की तारीफ करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति बिडेन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के असाधारण संरक्षक हैं। कमांडर इन चीफ के रूप में, उन्होंने रक्षा विभाग और अमेरिकी सेना के प्रति अपनी गहन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता दिखाई है, और मैं उनके नेतृत्व के लिए बहुत आभारी हूं। हमारी विदेश नीति के सबसे महान विचारकों में से जो बाइडन भी एक हैं।

ओबामा ने कहा कि हम अनजान राहों पर आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी के नेता कुछ ऐसा करेंगे, जिससे सर्वश्रेष्ठ नामांकन सामने आएगा। मुझे विश्वास है कि जो बाइडन का एक समृद्ध, उदार और एकजुट अमेरिका का विजन अगस्त में होने वाले डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में दिखाई देगा। ओबामा बोले जो बाइडन संघर्ष से पीछे हटने वाले नेता नहीं हैं, लेकिन अब मशाल अगले दावेदार को थमाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें लगा कि यह अमेरिका के लिए सबसे सही फैसला है। यह बाइडन का देश के प्रति प्यार का सबूत है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने राष्ट्रपति पद की रेस से हटने का एलान कर दिया है। पहली डिबेट में ट्रंप के सामने कमजोर पड़ने के बाद से ही जो बाइडन पर राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर होने का भारी दबाव पड़ रहा था, लेकिन खुद बाइडन पीछे हटने को तैयार नहीं थे। रविवार को चौंकाते हुए बाइडन ने अचानक से पीछे हटने का एलान किया। जो बाइडन के इस फैसले की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जमकर तारीफ की है।

बीत गया आधा जुलाई....... एनसीईआरटी की किताबें नहीं आईं

मंहगे दामों में निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने को मजबूर अभिभावक

नई दिल्ली (ईएमएस)। स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद भी कई अभिभावकों की शिकायत है कि बाजारों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की किताबें ही नहीं मिल रही हैं। अभी जुलाई का आधे से अधिक बीत जाने के बाद बाजार में किताब नहीं आई हैं। लिहाजा पेरेंट्स को निजी प्रकाशकों से अच्छे खासे पैसे देकर किताबें खरीद रहे हैं।

एक अभिभावक ने बताया कि एनसीईआरटी की जो किताब 50 से 70 रुपए में मिल जाती है, अब उसके लिए 200 से 250 देना पड़ रहा है। निजी प्रकाशकों से ली गई ये किताबें अपेक्षाकृत काफी महंगी हैं। इससे अभिभावकों की जेब पर बोझ पढ़ रहा है। निजी प्रकाशकों की किताबें दो से तीन गुना महंगी हैं। इस साल 5 से 10 प्रतिशत कीमत बढ़ी है। कक्षा 9 से 12 की एनसीईआरटी किताब का सेट 600-1000 रूपए में आ जाता है, जबकि निजी प्रकाशकों की पुस्तक का सेट 2000 से 2500 रुपए तक मिलता है।

पढ़ाई शुरू होने के कारण अभिभावकों को मजबूरन महंगी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। बुक सैलर ने कहा कि पहले एनसीईआरटी की योजना थी कि सभी ग्रेड के लिए नई किताबों को लाएंगे जबकि बाद में क्लास 6 से आगे की कक्षाओं में मौजूदा करिकुलम जारी रहेगा। हर सीजन में एनसीईआरटी किताबों की कमी रहती है। यूपी की तरह सरकार को एक तय रेट फिक्स कर प्रिंटिंग की अनुमति देनी चाहिए ताकि किताबों की कमी ना होने पाए। इस कमी का फायदा उठाते हुए किताबों के दाम बढ़ा दिये जाते हैं।

नीट में आज फिर सुनवाई ..... आईआईटी दिल्ली को दिया ये काम

-तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का आदेश

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर सुनवाई कर सोमवार को आईआईटी दिल्ली से कहा है कि वे नीट के विवादित प्रश्न से जुड़े विषय के तीन विशेषज्ञों की समिति बनाए जो इसके सही उत्तर पर राय देगी। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के विवादित प्रश्न के सही उत्तर पर राय बनाने के लिए संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का आदेश दिया है। कुछ छात्रों ने प्रश्न संख्या 19 के दो विकल्पों के लिए अंक देने के एनटीए के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता छात्र का कहना है कि नेगेटिव मार्किंग के डर से उस प्रश्न को छोड़ दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई शुरू होते ही पूछा कि नीट के सेंटर व शहर आधिरित रिजल्ट से क्या निकला? याचिकाकर्ता के वकील नरेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हमने डेटा पर आधारित नोट सब्मिट कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि नीट का पेपर परीक्षा के दिन 5 मई से दो दिन पहले ही लीक हो चुका था। उन्होंने कहा कि नीट का पेपर 3 मई को या उससे पहले लीक हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के बयानों से साफ होता है कि नीट पेपर लीक 4 मई से पहले हुआ। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ नीट को लेकर दायर 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की।

जम्मू में शौर्य चक्र विजेता के घर आतंकी हमला

जम्मू (ईएमएस)। जम्मू के राजौरी के घोंधा में सोमवार सुबह आतंकियों ने एक शौर्य चक्र विजेता के घर पर हमला किया। घटना सुबह 3:10 बजे हुई। हमले की खबर लगते ही 63 आरआर आर्मी कैंप से आई टुकड़ी ने जवाबी कार्रवाई की और एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है।

शौर्य चक्र विजेता की पहचान परशोत्तम कुमार के रूप में हुई है। उन्हें पिछले महीने दो आतंकियों को मारने के बाद यह सम्मान मिला था। परशोत्तम कुमार विलेज डिफेंस गार्ड भी हैं। आतंकी हमले में एक जवान और परशोत्तम कुमार के चाचा घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

भारत सुखोई विमानों को करेगा अपग्रेड, 2055 तक भर सकेंगे उड़ान

-कई खूबियों के साथ पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को देंगे टक्कर

नई दिल्ली,(ईएमएस)। भारत अपने सुखोई-30एमकेआई लड़ाकू विमानों को और शक्तिशाली बनाने में जुटा है। रक्षा मंत्रालय ने 84 सुखोई जेट को और शक्तिशाली बनाने के लिए करीब 63,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इन लड़ाकू विमानों को अपग्रेड के बाद ये सुखोई जेट अगले 30 साल तक आसमान में दुश्मनों को धूल चटा सकेंगे। इसमें जेट में अडवांस्ड रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार और मल्टी-सेंसर फ्यूजन जैसी कई खूबियां होगी। इसके बाद ये सुखोई जेट पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को टक्कर दे सकेंगे। सूत्र ने बताया कि ये अपग्रेडेड सुखोई जेट 2055 तक उड़ान भर सकेंगे।

वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जबकि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। हर स्क्वाड्रन में 16-18 जेट होते हैं। ऐसे में इन सुखोई जेट का अपग्रेड होना ज़रूरी है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) अगले 15 सालों में 84 सुखोई जेट को अपग्रेड करेगा। सीसीएस से मंजूरी मिलने के बाद, इसके डिजाइन और विकास में सात साल का समय लगेंगे। इसके बाद जेट को बैचों में अपग्रेड करके वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

भारत के पास अभी 259 सुखोई जेट हैं, जो उसकी लड़ाकू क्षमता की रीढ़ हैं। इनमें से ज़्यादातर जेट एचएएल ने रूस से लाइसेंस लेकर बनाए हैं। इसके अलावा दुर्घटनाग्रस्त हुए जेट की भरपाई के लिए 11,500 करोड़ रुपए में 12 नए सुखोई जेट और उनके उपकरण खरीदे जा रहे हैं। एक अन्य सूत्र ने बताया कि अगले 15 साल में भारत के पास खुद का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। इसकी तकनीक का इस्तेमाल पहले 84 जेट के बाद अपग्रेड किए जाने वाले सुखोई जेट में किया जाएगा।

इस अपग्रेड में सुखोई जेट में स्वदेशी 'विरूपाक्ष' एईएसए रडार लगाए जाएंगे, जो मौजूदा रडार की तुलना में 1.5 से 1.7 गुना ज़्यादा दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगा सकेंगे। इसके साथ ही जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाले एस्तरा-3 एयर-टू-एयर मिसाइल भी लगाए जाएंगे, जो 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। वायुसेना अभी 100 किलोमीटर तक मार करने वाली एस्तरा-1 मिसाइलों को शामिल कर रही है। वहीं डीआरडीओ 160 किमी तक मार करने वाली एस्तरा-2 और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रणोदन वाली एस्तरा-3 मिसाइल विकसित कर रहा है।

एक सूत्र ने बताया कि फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम को छोड़कर अपग्रेड किए गए सुखोई जेट के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स स्वदेशी होंगे। इसमें बेहतर एल्गोरिदम वाले तीनों मिशन कंप्यूटर शामिल हैं। कुल मिलाकर, अपग्रेड किए जाने वाले 51 सिस्टम में से 30 एचएएल द्वारा, 13 डीआरडीओ द्वारा और आठ निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाएंगे। अभी 40 सुखोई जेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए अपग्रेड किया है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है और जल्द ही 800 किमी वाले वर्जन को भी शामिल किया जाएगा।

शरणार्थियों को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार करती है कोई भी राज्य नहीं

-बांग्लादेशियों को शरण देने के ममता बनर्जी के बयान पर रविशंकर भड़के

नई दिल्ली,(ईएमएस)। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश के लोग अगर बंगाल आना चाहेंगे तो वह उन्हें शरण देंगी। इस पर सियासत शुरु हो गई है। ममता के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह वहीं ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने सीएए के तहत हिंदू, सिख और पारसियों को मिलने वाली नागरिकता का विरोध किया था।

रविशंकर ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश के लोगों को वह बंगाल में शरण देंगी। यह ममता वहीं हैं, जिन्होंने सीएए के मुद्दे पर कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख और पारसी शरणार्थियों को बंगाल में शरण नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने हमेशा ही सीएए का विरोध किया है। शरणार्थियों को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार करती है। कोई भी राज्य ऐसा फैसला नहीं ले सकता है। उन्होंने 1971 युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान भी शरणार्थियों को शरण देने का फैसला केंद्र सरकार ने ही किया था। बांग्लादेश में जो भी चल रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है। ममता ने कहा कि हिंदुस्तान के संबंध बंगाल के साथ अच्छे हों, इस बयान का क्या मतलब है।

अर्जेंटीना में डेंगू के करीब साढ़े पांच लाख मामले दर्ज

ब्यूनस आयर्स (ईएमएस)। अर्जेंटीना में इस साल अब तक डेंगू के पांच लाख 27 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 गुना अधिक मामले दर्ज हुए हैं, हालांकि हाल में मामलों में कमी आई है।

मंत्रालय केनए राष्ट्रीय महामारी विज्ञान बुलेटिन के अनुसार, इस वर्ष के पहले 28 हफ्तों में स्वास्थ्य अधिकारियों ने 527,517 मामले दर्ज किए।

वाइडेन चुनाव से पीछे हट गए लेकिन ट्रंप को चुनौती भी दे गए

वॉशिंगटन(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडन हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते थे। उनकी इच्छा थी एक बार फिर राष्ट्रपति बनें,लेकिन उनकी सेहत और इंटरनली प्रेशर के चलते उन्हे चुनावी रेस से बाहर होना पड़ा है। बाइडेन ने पीछे हटने का ऐलान करते हुए कमला हैरिस का नाम आगे बढ़ाकर एक चुनौती जरुरी खड़ी कर दी है। अब देखना यह है कि कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार बनेंगी या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप को रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच ट्रंप और उनके समर्थकों का दावा है कि कमला हैरिस को हराना उनके लिए और भी आसान होगा। हालांकि यह उतना आसान भी नहीं होने जा रहा है। बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से हटने ऐलान के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने कहा कि कमला हैरिस को हराना और भी आसान होगा। इसको लेकर ट्रंप समर्थकों की अपनी दलील है। उनका कहना है कि जो बाइडेन की तमाम नीतियों के लिए कमला हैरिस ही जिम्मेदार हैं। एक तीस सेकंड का ऐड भी चलाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कमला हैरिस जानती थीं कि जो बाइडेन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने काम किया और देखिए क्या है। बॉर्डर पर घुसपैठ हो रही है, महंगाई चरम पर पहुंच गई है और अमेरिकियों के सपनों का अंत हो चुका है। असल में बाइडेन के कार्यकाल में सीमा से घुसपैठ, बढ़ती महंगाई और महंगे होम लोन कुछ बेहद चर्चित मुद्दे हैं।

जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीजें आसान हो गई थीं। ट्रंप के ऊपर हुए हमले के बाद सहानुभूति की लहर भी उनके पक्ष में जा रही थी। लेकिन अगर कमला हैरिस के रूप में नया विपक्षी ट्रंप के सामने आता है तो उन्हें रणनीतियों में भी बदलाव करना होगा। इस बीच ट्रंप समर्थक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ने भी बदलते सिनैरियों के हिसाब से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उसका कहना है कि अब वह ट्रंप विरोधी टीवी ऐड्स को हटाने वाला है। इसकी जगह, एरिजोना, जॉर्जिया, नेवाडा और पेन्सिलवेनिया में नए विज्ञापन चलाए जाएंगे, जो कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए जाने जाते हैं। शनिवार को भी उन्होंने कुछ इसी अंदाज में कमला हैरिस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मैं तो उसे लॉफिंग कमला कहता हैं। आपने कभी ऐसी हंसी देखी है? वह क्रेजी है।

म्यांमार में बचाए गए 8 भारतीय नागरिक

यंगून (ईएमएस)। यंगून में भारतीय दूतावास ने कहा कि म्यांमार के म्यावाडी के हापा लू क्षेत्र में नौकरी घोटाले के शिकार आठ भारतीयों को बचाया गया है। भारतीय दूतावास ने उस देश में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय नागरिकों से सावधान रहने को कहा है, ताकि वे फर्जी या अवैध रोजगार के लालच में न फंसें। दूतावास ने कहा कि हापा लू, म्यावाड्डी में एक घोटाला केंद्र के पीड़ित 8 भारतीय नागरिकों को बचाया गया और सुरक्षित रूप से म्यांमार पुलिस/आव्रजन को सौंप दिया गया।

पिछले महीने एक सलाह में दूतावास ने कहा कि म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर म्यावाडी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट सक्रिय है और भारतीयों से क्षेत्र में नौकरी की पेशकश लेने से पहले सावधानी बरतने का आग्रह किया।दूतावास ने कहा कि म्यांमार-थाईलैंड सीमा पर म्यावाड्डी क्षेत्र में सक्रिय अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट का शिकार बनने वाले भारतीय नागरिकों की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

चुनाव अभियान के बीच में राष्ट्रपति की उम्मीदवारी छोड़ना अमेरिका में पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना

वाशिंगटन,(ईएमएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की एक घोषणा ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया भी चौंका दिया। उन्होंने घोषणा कि वह राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन की घोषणा के बाद ही उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर सामने आने की चर्चा जोरों पर है तो वहीं बाइडेन ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है।

इसी बीच अमेरिकी में राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास पर नजर डालें तो यह पहली बार नहीं है कि पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति ने दूसरी बार सत्ता में वापसी करने का विचार चुनाव अभियान के बीच ही छोड़ दिया हो और खुद को इस रेस से बाहर कर लिया हो। रविवार देर रात को जिस तरह का फैसला जो बाइडेन ने लिया उस तरह की घटना अमेरिका के सियासी इतिहास में साल 1968 में भी हो चुकी है।

1968 में, राष्ट्रपति चुनाव के बीच राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने उम्मीदवारी से पीछे हटने का फैसला करके सबको चौंकाया था। उन्होंने यह घोषणा वियतनाम युद्ध के बीच में की थी। 1968 में जॉनसन ने महसूस किया था कि वह पार्टी पर नियंत्रण खो रहे हैं और पार्टी के अंदर ही चार विरोधी गुट बन गए थे। वियतनाम युद्ध पर अलग-अलग रुख उन मुद्दों में से एक था जिसने पार्टी को बांट दिया था, वहीं जॉनसन को युद्ध जीतने का भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इसके अलावा वह पार्टी को एकजुट बनाए रखने में भी असमर्थ थे। इसके अलावा जॉनसन अपने गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित थे। वह यह भी मान कर चल रहे थे कि वह एक और कार्यकाल तक जीवित नहीं रह पाएंगे।

28 मार्च को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और राजनीतिक पकड़ के ढीली होने के साथ राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने पर विचार किया और जोसेफ ए. कैलिफ़ानो जूनियर और हैरी मैकफरसन के साथ इस पर चर्चा की. इस मुलाकात के तीन दिन बाद जॉनसन ने खुद को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अलग करने का ऐलान कर दिया था।

इसके बाद उपराष्ट्रपति रहे ह्यूबर्ट हम्फ्री को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने उन्हें हरा दिया और राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। 5 नवंबर 1968 को रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे।

इस सप्ताह 16 नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस सप्ताह 16 नई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होंगी जिससे लोगों को शुरूआती दौर में ही निवेश का मौका मिलेगा। सप्ताह के शुरूआत में एसएमई (छोटी, मझली कंपनिया) सेक्टर की 8 कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। इन कंपनिया का बाजार से 809 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। निवेशकों को इनमें कम से कम 13,500 रुपये निवेश करना होगा। इसके साथ ही शेयर बाजार में 8 नई कंपनियां लिस्ट होंगी। ब्लूमबर्ग के अनुसार इस साल भारतीय शेयर बाजार में जो नए शेयर लिस्ट हुए, उन्होंने औसतन 57 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं पूरे ऐशिया प्रशांत में नए शेयरों ने 32 फीसदी का रिटर्न दिया है। 2024 में आए नए आईपीओ 12 गुना अधिक सब्सक्राइब हुए क्योंकि रिटेल निवेशक इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस सप्ताह सोमवार को श्री एम पेपर बोर्ड, प्राइजर विजटेक, एविया कमो. और सिटी पॉली प्लास्ट शेयर मार्केट में लिस्ट होंगी। वहीं मंगलवार को टुनवाला ई-मोटरास और बुधवार को मैकाब्स टेक्नो और कटारिया इंडस्ट्रीज लिस्ट होंगी। शुक्रवार को आखिरी कारोबारी दिन में सैनस्टार का खाता खुलेगा। 8 में से 4 आईपीओ के लिए 2 लाख से ज्यादा का निवेश करना होगा। बाजार में कंज्यूमर, हेल्थ केयर और टेक सेक्टर की कंपनियां आईपीओ लाने में सबसे आगे हैं। ब तक भारतीय बाजार में आई 36 बड़ी कंपनियों ने रिटेल निवेशकों से 92,000 करोड़ रुपये जुटाए है। इस दौरान केवल आईपीयो ने करीब 32,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। अगले छह महीनों में हुंडई इंडिया, विशाल मेगामार्ट समेंत 15 बड़ी कंपनिया आईपीओ लाएंगी।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद सेंसेक्स 103 , निफ्टी 22 अंक नीचे आया

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। बजट से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक महिंद्रा बैंक में भारी बिकवाली रही। इससे इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी नीचे आये। वहीं दुनिया भर के बाजारों के मिले कमजोर संकेतों से भी निवेशकों से सतर्कता बरती।

दिन भर के गिरावट के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 102.57 अंक करीब 0.13 फीसदी नीचे आकर 80,502.08 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21.65 अंक तकरीबन 0.09 फीसदी नीचे आकर 24,509.25 पर बंद हुआ।

आज के कारोबार में सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर नुकसान के साथ ही नीचे आकर बंद हुए। कोटक बैंक, रिलायंस, आईटीसी, एसबीआई और एचसीएल टेक सेंसेक्स के सबसे अधिक नुकसान वाले शेयर रहे। वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्लयू स्टील, टाइटन और अदाणी पोर्ट्स के शेयर नुकसान में रहे।

वहीं दूसरी ओर सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आकर बंद हुए। एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील और एंडएमएम सेंसेक्स के शीर्ष पांच लाभ वाले शेयर रहे। इसके अलावा, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, एलएंडटी, मारुति, इंफोसिस, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और एचयूएल के शेयर लाभ में रहे।

एशियाई बाजारों में, सियोल, टोक्यो और शंघाई निचले स्तर पर बंद हुए, जबकि हांगकांग सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ। दोपहर के सत्र में यूरोपीय बाजार बढ़त पर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 1,506.12 करोड़ रुपये की इक्विटी खरीदी। इससे पहले आज सुबह वै?श्विक बाजारों से ?मिले खराब संकेतों की वजह से सप्ताह के पहले कारोबारी ?दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत ?गिरावट के साथ हुई। बीएसई सेंसेक्स 463 अंक गिरकर 80,141 अंकों पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी50 सूचकांक 147 अंकों की गिरावट के साथ 24,383 अंकों पर आ गया। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स ने 81,587 और निफ्टी ने 24,853 का स्तर छुआ। हालांकि, इसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। सेंसेक्स 738 अंक की गिरावट के साथ 80,604 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 269 अंक की गिरावट रही, ये 24,530 के स्तर पर बंद हुआ था।

कनाडा में रोजगार के लिए भटक रहे भारतीय, वतन वापसी की कर रहे तैयारी

टोरंटो(ईएमएस)। कनाडा में भी रोजगार की समस्या है। यहां भारतीयों को इस समय रिकॉर्ड बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। कनाडा में हाल ही में बसे आप्रवासियों के लिए बेरोजगारी दर जून में 12.6 प्रतिशत थी। यह पिछले 10 वर्षों का सबसे खराब बेरोजगारी स्तर है। कनाडा में स्थायी नागरिकता हासिल करने वालों में सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। इसलिए भारतीयों पर ही इस बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा पड़ने की संभावना है। हालांकि मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि पिछले आठ महीनों में कनाडा की जस्टिन टूडो की सरकार ने भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों से उनकी समस्या हल नहीं होगी और कनाडा से रिवर्स माइग्रेशन अभी दूर की बात है।

रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में ब्रैम्पटन में कनाडाई पंजाबी सांस्कृतिक सोसायटी के एक सेमिनार में पंजाबी विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर कुलदीप सिंह ने कहा कि कनाडा में छात्रों की संख्या में कमी आई है लेकिन रिवर्स माइग्रेशन तभी संभव है जब भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति कनाडा से बेहतर होगी। इस स्थिति की फिलहाल कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। कुलदीप सिंह ने कहा कि कोई की शख्स तभी वापस लौटने की कल्पना कर सकता है, जब उसे अपने देश में ज्यादा असवरों दिखे। यह अभी भी एक कल्पना है, वास्तविकता से बहुत दूर है। विश्व विकास रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रोफेसर सिंह ने कहा कि अंतररा राष्ट्रीय छात्रों के रूप में दुनियाभर में जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2000 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 41 प्रतिशत हो गई है। कनाडाई आव्रजन परामर्श के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय छात्रों के कनाडा प्रवास में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केवल 2019 में 198,235 छात्र भारत से कनाडा आए और इसमें से 71 प्रतिशत अनुपात पंजाब से थे।

कनाडा की राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसी स्टैटिस्टिक कैनेडा के अनुसार 12.6 प्रतिशत की बेरोजगारी दर 2023 से चार प्रतिशत कम है। कनाडाई मूल के लोगों में बेरोजगारी 5.5प्रतिशत है। साल 2023 में यह 5प्रतिशत थी। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के अनुसार, नए आंकड़े बताते हैं कि आप्रवासियों के बीच बेरोजगारी दर 2014 के बाद से सबसे ज्यादा है। आप्रवासियों में बढ़ती बेरोजगारी से भारतीयों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना इसलिए है क्योंकि हाल के वर्षों में कनाडा की सबसे ज्यादा नागरिकता भारतीयों को ही मिली है। साल 2023 में कनाडा ने 4,71, 810 लोगों को स्थायी नागरिकता दी। इनमें से 1,39,785 या लगभग 30प्रतिशत भारतीय थे। इमिग्रेशन, रेफ्युजीज़ एंड सिटीजनशिप कैनेडा के आंकड़ों के अनुसार, 2019 के बाद से कनाडा आए 18,41,250 नए स्थायी निवासियों में से 5,14,435 भारतीय थे। स्टैटिस्टिक कैनेडा ने एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया कि जून 2024 में 14 लाख बेरोजगार लोग थे, जो पिछले महीने से 42,000 (+3.1 प्रतिशत) ज्यादा हैं। कनाडा में कंपनियां उच्च ब्याज दरों से जूझ रही हैं। इसी वजह से वे पिछले दो सालों में नियुक्तियां करने में झिझक रही हैं। आप्रवासियों की भारी आमद के कारण कनाडा की जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है।

कमला का समर्थन कर रामास्वामी ने भारतीय-अमेरिकियों के प्रतिनिधित्व को बड़ी छंलाग

वाशिंगटन (ईएमएस)। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक नेता अश्विन रामास्वामी ने पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया। रामास्वामी ने कहा,''यह (कमला का राष्ट्रपति चुना जाना) भारतीय-अमेरिकियों और एएपीआई (एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह निवासी) के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ी छलांग होगा।''

रामास्वामी की यह टिप्पणी तब आई, जब बाइडन ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जताकर डेमोक्रेटिक पार्टी की नई उम्मीदवार के रूप में भारतीय-अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस के नाम की सिफारिश की।

रामास्वामी ने कहा, ''उपराष्ट्रपति कमला अमेरिका की पहली भारतीय-अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में इतिहास रचेंगी। यह अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी और एएपीआई समुदाय के प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ी छलांग होगा और मेरे जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा साबित होगा। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन हैरिस की तरह मेरी मां भी चेन्नई के बेसेंट नगर से हैं, जो मेरे लिए बेहद खास बनाता है। रामास्वामी ने कहा कि वह राष्ट्रपति बाइडन के शानदार नेतृत्व के लिए उनके आभारी हैं और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए अगले डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस के नाम का समर्थन करते हैं।

सोना 73 हजार के पार, चांदी में भी गिरावट

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने के वायदा कारोबार की शुरुआत सोमवार को तेजी के साथ हुई, जबकि चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 73,150 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 89,600 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 171 रुपये की तेजी के साथ 73,161 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 179 रुपये की तेजी के साथ 73,169 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत आज सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 5 रुपये की गिरावट के साथ 89,641 रुपये पर खुला। इस समय यह 66 रुपये की गिरावट के साथ 89,580 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2403.70 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,399.10 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 10.40 डॉलर की तेजी के साथ 2,409.50 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 29.42 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव भी 29.29 डॉलर था। इस समय यह 0.10 डॉलर की तेजी के साथ 29.39 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चीन के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर घटाई

बैंकॉक (ईएमएस)। चीन के केंद्रीय बैंक ने अपनी पांच वर्षीय प्रमुख ऋण दर और एक वर्षीय दर दोनों में कटौती कर दी है। यह फैसला उसके संपत्ति क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ?किया गया है। पांच साल की दर में 10 आधार अंकों की कटौती की गई जिससे यह 3.95 प्रतिशत से 3.85 प्रतिशत हो गई है। एक साल की दर को 3.45 प्रतिशत से घटाकर 3.35 प्रतिशत कर दिया गया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंकों के लिए अपनी मध्यम अवधि की ऋण सुविधा के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को भी कम कर दिया है। बैंक ने कहा कि इसका मकसद बॉन्ड बाजार पर दबाव कम करना है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से गति हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। इसमें संपत्ति बाजार में मंदी एक बड़ी बाधा रही है। आर्थिक वृद्धि दर पिछली तिमाही में गिरकर 4.7 प्रतिशत हो गई, लेकिन वर्ष की पहली छमाही के लिए यह सरकार के लक्ष्य (पांच प्रतिशत) के आसपास बनी रही।

टाइटैनिक डूबने से हुई कुल मौतों का रहस्य अब भी बरकरार

लंदन (ईएमएस)। इतिहास की हैरान करने वाली घटनाओं में शुमार विशाल जहाज टाइटैनिक का डूबना शामिल है। 112 साल पहले हुई इस हादसे की भविष्यवाणी तक की चर्चा आज भी होती है। लेकिन यह आज भी सुर्खियों में रहता है, इसे लेकर कई तरह के रहस्य हैं। इन्हीं में से एक रहस्य इसके डूबने से मरे इंसानों के अवशेषों का गायब रहना है। साल 1985 में इसका मलबा पहली बार देखा गया था। तब से अब तक इसके कई तरह की जांच हो चुकी हैं, लेकिन अब तक इसमें एक भी इंसानी अवशेष, यहां तक कि हड्डियां भी नहीं मिली है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा 1985 में समुद्र विज्ञान के प्रोफेसर और अमेरिकी नौसेना अधिकारी रॉबर्ट बैलार्ड ने अपने गहरे समुद्र के रोबोट, आर्गोस का उपयोग करके जहाज खोज निकाला था। इतने साल बीत जाने का मतलब है कि शव सड़ चुके या समुद्री जीवों ने खा लिया, फिर भी आप उम्मीद करते हैं कि जहाज और उसके आस-पास के समुद्री तल में कंकाल मौजूद हो।

हड्डियों और कंकालों की कमी का कारण टाइटैनिक की गहराई है जिस पर वह रुका था। यह लगभग 3,800 मीटर की गहराई पर समुद्र तल पर स्थित है और उस गहराई पर पानी की रासायनिक संरचना हड्डियों पर पड़ने वाले असर को बदल देती है। प्रोफेसर बैलार्ड, जिन्होंने बिस्मार्क के मलबे की भी खोज की थी, ने बताया, आपको जिस मुद्दे से निपटना है, वह यह है कि लगभग 914 मीटर से कम गहराई का समुद्री पानी कैल्शियम कार्बोनेट से घुला हुआ या भरा हुआ होता है, जो कि ज्यादातर, हड्डियों से बना होता है। जहां टाइटेनिक डूबा वहां हड्डियां घुल कर पहले ही इधर उधर हो चुकी होंगी।

मंगल ग्रह पर रोवर से चट्टान टूटी...फिर वैज्ञानिकों को मिला पीला खजाना

वॉशिंगटन (ईएमएस)। मंगल ग्रह के शोध में नासा लंबे समय से लगा हुआ है। इस बीच नासा को मंगल ग्रह पर एक ऐसी चीज मिली है, जो किसी खजाने से कम नहीं। मंगल ग्रह की एक चट्टान में यह पीला खजाना निकला है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने गलती से चट्टान को तोड़ दिया था। चट्टान टूटने के बाद रोवर को इसमें से हैरान करने वाली चीज दिखाई दी। नासा का रोवर 899 किलोग्राम का है। जब इतने भारी रोवर का पहिया एक चट्टान पर पड़ा, तब वह टूट गया। रोवर के कैमरों ने जब चटटान को देखा तब शुद्ध सल्फर के क्रिस्टल मिले।

पीले रंग के ये क्रिस्टल चमक रहे थे। हालांकि मंगल पर सल्फेट काफी आम हैं, लेकिन यह पहली बार है कि लाल ग्रह पर सल्फर अपने शुद्ध रूप में मिला है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस चट्टान का गेडिज वालिस चैनल में मिलना है। यह इलाका उन चट्टानों से भरा है, जो संदिग्ध रूप से सल्फर से भरी हो सकती हैं। यह खोज सुझाव देती है कि कुछ स्थानों पर मौलिक सल्फर प्रचुर मात्रा में हो सकता है। नासा वैज्ञानिक अश्विन वासवदा का कहना है, शुद्ध सल्फर से बने पत्थरों का क्षेत्र ढूंढना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है।

उन्होंने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अब हमें इसे समझना होगा। अजीब और अप्रत्याशित चीजों की खोज ही ग्रहों की खोज को इतना रोमांचक बनाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सल्फेट्स तब बनते हैं जब सल्फर पानी में अन्य खनिजों के साथ मिश्रित होता है और फिर वाष्पित हो जाता है, जिससे सल्फेट खनिज पीछे रह जाते हैं। ये खनिज मंगल के इतिहास, विशेष रूप से इसके पानी वाले इतिहास और समय के साथ इसके मौसम के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे सकते हैं।

हालांकि, शुद्ध सल्फर को बनने के लिए बहुत खास परिस्थितियों की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति जिसके बारे में मंगल के इस क्षेत्र में होना वैज्ञानिकों ने कभी नहीं सोचा था। मंगल पर मिले यह सल्फर क्रिस्टल दिखाते हैं कि लाल ग्रह पर बहुत कुछ ऐसा है, जिसके बारे में हमें कोई अनुमान नहीं है। यह समझना बेहद जरूरी है कि सभी जीवन के लिए सल्फर आवश्यक तत्व है। हालांकि मंगल पर सल्फर होना यह नहीं बताता कि यहां जीवन था।

गुजरात : चांदीपुरा वायरस से मृतकों की संख्या हुई 33, अब तक 84 संदिग्ध मामले मिले

गोंडल के राणसिकी और बनासकांठा के सुइगाम में 1-1 बालक की मौत

अहमदाबाद, 22 जुलाई (हि.स.)। राज्य में चांदीपुरा वायरस का कहर जारी है। सरकार अलर्ट मोड पर कार्रवाई में जुटी है। गांव से लेकर शहर तक यह वायरस पैर पसार चुका है। राज्य में मानसून की बरसात इस वायरस को फैलाने में मददगार है, इसलिए प्रशासन कई स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रहा है। हॉस्पिटलों में व्यवस्था स्टैंडबॉय रखी गई है, तो कई जगहों पर विशेष वार्ड में बच्चों का इलाज किया जा रहा है।

संक्रमण से यह बीमारी नहीं फैलती है, इस वजह से प्रशासन इसकी मूल वजह सैंड मक्खी को नियंत्रित करने में जुटा है। सोमवार को 3 बच्चों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई। सोमवार को बनासकांठा के सुइगाम, राजकोट के गोंडल के राणसिकी और देवभूमि द्वारका जिले में 1-1 बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही चांदीपुरा वायरस के संदिग्ध केस की संख्या बढ़कर 84 हो गई है। जानकारी के अनुसार राजकोट जिले की गोंडल तहसील के राणसिकी गांव में 7 वर्षीय बालक की तबियत बिगड़ने पर उसे रविवार को राजकोट के जनाना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बच्चे की सभी तरह की जांच कराई जा रही थी लेकिन रिपोर्ट आने से पूर्व ही सोमवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोंडल के राणसिकी गांव के सरपंच घनश्याम काछडिया ने एक बच्चे की मौत उसके घर में और दूसरे बच्चे की मौत हॉस्पिटल में होने की जानकारी दी है। इस तरह उन्होंने दो मौत का दावा किया है। इसके अलावा बनासकांठा के सुईगांव में चांदीपुरा के संदिग्ध मरीज की सोमवार सुबह मौत हो गई है।

सूरत में 1 केस और मौत 0, राजकोट में 4 केस और मौत 3, साबरकांठा में 8 केस और मौत 2, अरवल्ली में 6 केस और मौत 3, महीसागर में 2 केस और मौत 1, खेडा में 6 केस और मौत 1, मेहसाणा में 6 केस और मौत 2, सुरेन्द्रनगर में 3 केस और मौत 1, अहमदाबाद में 6 केस और मौत 3, गांधीनगर में 5 केस और मौत 1, पंचमहाल में 11 केस और मौत 4, जामनगर में 5 केस और मौत 0, मोरबी में 4 केस और मौत 3, जामनगर में 3 केस और मौत 1, छोटाउदेपुर में 2 केस और मौत 0, दाहोद में 2 केस और मौत 2, वडोदरा में 1 केस और मौत 1, नर्मदा में 2 केस और मौत 0, बनासकांठा में 4 केस और मौत 3, वडोदरा महानगर पालिका में 2 केस और मौत 1, भावनगर में 1 केस और मौत 0, द्वारका में 1 केस और मौत 1, राजकोट महानगर पालिका में 2 केस और मौत 0, कच्छ में 1 केस और मौत 0 मिलाकर कुल 84 संदिग्ध मामले और 33 मौत हुई हैं।

देवभूमि द्वारका में भारी बारिश, हेलीकॉप्टर से चला रेस्क्यू ऑपरेशन

अहमदाबाद, 22 जुलाई

देवभूमि द्वारका की कल्याणपुर तहसील में मानसून की बारिश से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। तहसील के कई गांवों में पानी भरने से आवाजाही बंद हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के खेत तालाब और रास्ते नदी जैसी स्थिति में हो गए हैं। भारी बारिश के कारण कई लोगों के पानी में फंसने के बीच लोगों को हेली कॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया।

कल्याणपुर तहसील के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में 11 लोगों के पानी में फंसे होने की जानकारी पर प्रशासन ने सभी का रेस्क्यू किया है। केशवपुर गांव के 4 व्यक्ति, टंकारिया गांव के 4 व्यक्ति को प्रशासन ने पानी से बचाव किया। पानेली गांव के 3 व्यक्ति को हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। पानी भरने की जानकारी होने पर इस क्षेत्र के तहसीलदार और उप तहसीलदार घुटने तक पानी में जाकर लोगों के बचाव में जुटे रहे। द्वारका के कल्याणपुर गांव में मूसलाधार बारिश के कारण गांव में नदी बहने जैसे हालात हो गए हैं। कल्याणपुर में 8 इंच बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण गांव के बाजार, सड़क और खेतों में पानी भर गया है। घुटने तक पानी में जाकर लोग जरूरी कामकाज कर रहे हैं। सबसे अधिक हालत खराब पशुओं और मवेशियों को देखी गई। लोग-बाग अपने मवेशियों को बचाने में प्रयासरत देखे गए। भारी बारिश के कारण एक दर्जन से अधिक गांवों का सम्पर्क भी टूट गया है।

सौराष्ट्र में सोमवार को मूसलाधार बारिश हो रही है। द्वारका में भारी बारिश के कारण जन-जीवन ठप पड़ गया है। दक्षिण गुजरात में भी भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य की कुल 250 तहसीलों में से 139 तहसील में बारिश हुई है।

सूरत की पलसाणा में 6 इंच, बारडोली में 5.59 इंच, कामरेज में 4.69 इंच, मांडवी में 3.90 इंच, जूनागढ़ की मालिया हाटिया में 5.31 इंच, द्वारका में 5.31 इंच, राजकोट की उपलेटा में 5 इंच, गिर सोमनाथ की गिर गढ्डा में 4.72 इंच, वलसाड की वापी में 3.50 इंच, पोरबंदर की कुतियाणा में 3.43 इंच, वलसाड की कपराडा में 3.31 इंच, पोरबंदर के राणावाव में 3.27 इंच बारिश हुई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण : बांग्लादेश में फँसे 14 गुजराती छात्र सुरक्षित स्वदेश लौटे

गांधीनगर 22 जुलाई, 2024 : बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति में वहाँ फँसे गुजरात के छात्रों में से 14 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देशन में राज्य सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ तत्काल समन्वय स्थापित किया, जिसके चलते ये 14 गुजराती छात्र सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। श्री पटेल ने बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए विद्यार्थियों को वहाँ भड़की हुई हिंसा व अन्य घटनाओं के बीच से सुरक्षित अपने माता-पिता व परिवार तक पहुँचाने की व्यवस्था के लिए राज्य के प्रवासी गुजराती प्रतिष्ठान (एनआरजी फाउंडेशन) को तत्काल समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के चलते एनआरजी फाउंडेशन ने बांग्लादेश में फँसे विद्यार्थियों का विवरण प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9978430075 घोषित किया है। इतना ही नही; ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावक व परिजन अपने बच्चों की जानकारी प्राप्त कर सकें; इसके लिए ई-मेल आईडीर्ड्दिर्ल्र्ड्दर्ढ़र्ल्ड्र्.द्नग्ह पर भी विवरण मंगवाना शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशानिर्देशन में राज्य सरकार के इस प्रो-एक्टिव दृष्टिकोण के फलस्वरूप विद्यार्थियों के अभिभावकों-परिजनों ने एनआरजी फाउंडेशन का संपर्क कर विवरण दिया था। इस विवरण के आधार पर एनआरजी फाउंडेशन ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ सम्पर्क साधा और जिन 25 के करीब विद्यार्थियों का संपर्क हुआ, उन्हें गुजरात लाने की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कीं।

इन फलदायी प्रयासों के परिणामस्वरूप फिलहाल भरूच जिले के 7, अहमदाबाद व भावनगर के 2-2 और अमरेली, मेहसाणा तथा पाटण के 1-1 सहित कुल 14 छात्र बांग्लादेश से सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। श्री पटेल के निरंतर मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ परामर्श में रहते हुए शेष 11 छात्रों को वापस लाने की कवायद भी शुरू की है।

केन्द्रीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश की स्थिति के संदर्भ में एक एडवाइजरी जारी कर वहाँ बसने वाले भारतीय समुदाय के लोगों तथा छात्रों से लोकल ट्रैवल न करने तथा घर से बाहर कम से कम निकलने का अनुरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में किसी भी प्रकार की सहायता या तत्काल आवश्यकता लगने पर बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायुक्त तथा सहायक उच्चायुक्त के 24 घण्टे कार्यरत फोन नंबर घोषित किए हैं।

ये नंबर निम्नानुसार हैं : भारतीय उच्चायोग, ढाका , +880-1937400591 (व्हॉट्सएप भी) ,* सहायक भारतीय उच्चायोग, चाटगाँव ,+880-1814654797/+880-1814654799 (व्हॉट्सएप भी) ,* सहायक भारतीय उच्चायोग, राजशाही ,+880-1788148696 (व्हॉट्सएप भी), * सहायक भारतीय उच्चायोग, सिलहट ,+880-1313076411 (व्हॉट्सएप भी) ,* सहायक भारतीय उच्चायोग, खुलना ,+880-1812817799 (व्हॉट्सएप भी)

राजधानी गांधीनगर में IAS की पत्नी ने जहर खाकर दी जान

गांधीनगर, २२ जुलाई ।

गुजरात के एक आईएएस अधिकारी की अलग रह रही पत्नी ने रविवार को गांधीनगर में अधिकारी के घर के दरवाजे पर जहर खाकर दम तोड़ दिया । पिछले महीने यह आईएएस की पत्नी अपने गृहनगर तमिलनाडु के एक गैंगस्टर के साथ भाग गई थी । वहां एक बच्चे के अपहरण के मामले में भी वह शामिल थी । महिला का नाम सूर्या जे (४५) था । जहर खाने के बाद उसे इलाज के लिए की गुजरात की राजधानी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई । पुलिस के अनुसार, सूर्या ने शनिवार सुबह जहरीला पदार्थ निगला था । वह अपने पति रंजीत कुमार जे के घर पहुंची थी । यहां महिला से नाराज उसके पति ने अपने यहां के स्टाफ को निर्देश दिया था कि वे उसे घर में न आने दें ।

घटना गांधीनगर के सेक्टर-१९ की है । रंजीत कुमार गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी) के सचिव हैं । एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'रंजीत कुमार शनिवार को सूर्या के साथ तलाक की अर्जी को अंतिम रूप देने के लिए बाहर गए थे ।'

रंजीत ने स्टाफ को साफ कहा था कि सूर्या को किसी भी सूरत में अंदर न आने दें । वह यहां पहुंची और जबरन अंदर जाने का प्रयास किया लेकिन कर्मचारियों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया । इसस क्षुब्ध होकर उन्होंने (सूर्या) जहर खा लिया और १०८ (एम्बुलेंस हेल्पलाइन) पर कॉल किया । गांधीनगर के एसपी रवि तेजा वासमसेट्टी ने कहा कि सूर्या जे के पास पुलिस को तमिल में लिखा एक कथित सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उन्होंने विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया । पुलिस ने कहा कि जे सूर्या गैंगस्टर के साथ मदुरै के एक १४ वर्षीय लड़के के अपहरण में शामिल थी । हो सकता है कि मामले में तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सूर्या अपने पति के घर गई होगी ।

इस मामले में सूर्या का नाम उसके कथित प्रेमी और स्थानीय गैंगस्टर हाई कोर्ट महाराजा और उसके सहयोगी सेंथिल कुमार के साथ सामने आया । उन्होंने कथित तौर पर बच्चे की मां के साथ पैसे के विवाद में ११ जुलाई को लड़के का अपहरण कर लिया था । उन्होंने उसकी मां से २ करोड़ रुपये की फिरौती मांगी थी, लेकिन मदुरै पुलिस ने लड़के को बचाने में कामयाबी हासिल की । इसके बाद पुलिस ने सूर्या सहित सभी लोगों की तलाश शुरू कर दी ।

इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सूर्या ने रंजीत कुमार को छोड़ दिया था और करीब नौ महीने पहले हाई कोर्ट महाराजा नाम के गैंगस्टर के साथ भाग गई थी । एसपी वासमसेट्टी ने अपहरण मामले को एक कारक बताया । अधिकारी ने कहा, 'मुझे रिपोर्टों से पता चला कि उस पर (सूर्या) मदुरै में अपहरण का आरोप था, जिसके कारण उसे यह चरम कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा ।'

सूरत में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बाढ़ से तबाही

इस समय गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है । सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है । रविवार रात को सूरत में भी भारी बारिश हुई जिसके कारण सूरत के कई इलाकों में पानी भर गया है । खटोदरा इलाके में दुकानों और घरों में पानी घुस गया । इसके अलावा निचले इलाकों में भी भूस्खलन की हद तक पानी भर गया है । रविवार शाम से ही सूरत में बारिश शुरू हो गई । रविवार को छुट्टी होने के कारण परिवार के साथ बाहर निकले लोगों को तेज बारिश के कारण परेशानी हुई । सूरत के सरथाना, वराछा, अठवागेट, कतारगाम, उधना, रांदेर, अडाजण, वेसु और सचिन में पानी भर गया, जिससे कई सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया ।

रविवार को हुई भारी बारिश से सूरत में पानी भर गया, वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है । सूरत में रविवार सुबह से बारिश हो रही थी लेकिन बारिश नहीं हुई । रविवार को छुट्टी होने के कारण शाम को लोग परिवार के साथ बाहर भी निकले । मूसलाधार बारिश होते ही लोगों के गिरने की बारी आ गई । इसके अलावा भारी बारिश के कारण पानी भर गया और सड़कों पर पानी भर गया. जिसके कारण ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा ।

अहमदाबाद में पानी और मच्छर से होने वाली बीमारी की स्थिति बदतर हुई

अहमदाबाद, २२ जुलाई ।

गुजरात में मानसून का मौसम बहुत अच्छा रहता है । भारी बारिश के कारण राज्य में बाढ़ आ गई है । कुछ स्थानों पर पानी रिसता हुआ कीचड़ दिखाई देता है । फिर महामारी का डर बढ़ गया है । अहमदाबाद में पानी और मच्छर जनित बीमारी बढ़ गई है । जुलाई माह में शहर में डेंगू के साथ-साथ डायरिया-उल्टी और टाइफाइड के मामले बढ़े हैं ।

के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख डॉ । भाविन सोलंकी ने बताया कि जुलाई माह के २१ दिनों में डेंगू के ७९ मामले, दस्त-उल्टी के ९४० मामले, पीलिया के २२८ मामले, टाइफाइड के ४२३ मामले और हैजा के ३२ मामले सामने आए हैं । साधारण मलेरिया के १४, चिकनगुनिया के दो मामले सामने आए हैं । ४५०१ पानी के नमूनों की जांच की गई और उनमें से १५५ पानी के नमूने अनफिट आए हैं ।

इस साल अहमदाबाद में हैजा के मामले बढ़े हैं । शहर में अशुद्ध पेय जल की उपलब्धता के कारण डायरिया,पीलिया,हैजाऔर टाइफाइड के मामले बढ़े हैं । जहां प्रदूषित पानी आ रहा है, वहां इंजीनियरिंग विभाग को सूचना देकर लाइनें बदलने के निर्देश दिए गए हैं । क्लोरीन की गोलियां बांटी जा रही हैं । शहर के दाणी लीमड़ा, बहेरामपुरा, अमराईवाड़ी, लांभा, जशोदानगर और नारोल जैसे इलाकों में पिछले दो महीने से लगातार हैजा के मामले सामने आ रहे हैं । इस साल जनवरी से जुलाई तक हैजा के करीब १५५ मामले सामने आए हैं । साल २०२३ में जनवरी से दिसंबर तक सिर्फ ९५ मामले आए ।

चालू वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में पिछले सात महीनों में डायरिया और उल्टी के ७ मामले भी देखे गए हैं, जो वर्ष २०२३ की तुलना में अधिक हैं । इस साल जुलाई महीने में डायरिया और उल्टी के ७४३५ मामले सामने आए हैं ।

महिंद्रा की नई पेशकश का नाम होगा 'थार रॉक्स'

एसयूवीः इस एसयूवी को सोफिस्टिकेशन, परफॉरमेंस, खूबसूरती, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ मिश्रण प्रदान करने के लिए डिजाइनकिया गया है और इस तरह महिंद्रा 'थार रॉक्स' बेहतरीन एसयूवी के रूप में तैयार हुईहै।

मुंबई, 20 जुलाई, 2024: भारत की अग्रणी एसयूवी विनिर्माता, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने आज अपने ताज़ातरीन एसयूवी के ब्रांड नाम की घोषणा की। इसे महिंद्रा 'थार रॉक्स' का नाम दिया गया है। ऑटोमोटिव उद्योग में नए मानक स्थापित करने और प्रामाणिक एसयूवी के विनिर्माता के रूप में जाने जाने वाले महिंद्रा की ताज़ातरीन पेशकश – बेहतरीन एसयूवी है। यह एक ऐसा वाहनहै जिसे सोफिस्टिकेशन, परफॉरमेंस, खूबसूरती, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी का बेजोड़ मिश्रण प्रदान करने के लिए डिजाइनऔर इंजीनियर किया गया है।'थार रॉक्स' थार पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है।

एमएंडएम लिमिटेड के ऑटोमोटिव सेक्टर के अध्यक्ष, वीजय नाकरा ने कहा, ''अपने विशिष्ट डिजाइन, प्रीमियम क्वालिटी, उन्नत टेक्नोलॉजी, बेहतर परफॉरमेंस, सोफिस्टिकेशन और सुरक्षा के साथ 'थार रॉक्स' बेहतरीन एसयूवी है। मशहूर ब्रांड थार की मुख्य विशेषताओं को बनाए रखते हुए 'थार रॉक्स' रॉकस्टार जैसे विशाल व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है और यह एसयूवी श्रेणी में हलचल मचा देगी।''

पिछले दो वर्षों में जीएचसीएल फाउंडेशन के वीटीआई प्लेसमेंट में वृद्धि हुई है

अहमदाबाद, 22 जुलाई, 2024: जीएचसीएल फाउंडेशन के व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (वीटीआई) ने ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने और महिलाओं को रोजगार में समान अवसर प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले दो वर्षों में, वीटीआई ने 2,349 लोगों को प्रशिक्षित किया है और लगभग 85ऱ की प्लेसमेंट दर हासिल की है, जिनमें से 2,046 उम्मीदवारों ने विभिन्न उद्योगों में रोजगार हासिल किया है।

गुजरात के गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में सूत्रपाड़ा, जाफराबाद, काज-वेलन, तलाला, मोटा लाजा और पोर्ट विक्टर में स्थित, ये वीटीआई गुजरात के गांवों में युवाओं को रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। कच्छ जिले में विस्तार की योजना के साथ, ये संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिक से अधिक युवाओं को सशक्त बनाने में मदद करेंगे।

वित्त वर्ष 2024 में जीएचसीएल फाउंडेशन के वीटीआई में लगभग 1,590 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुना है। वीटीआई पाठ्यक्रम में 70ऱ प्रैक्टिकल, 15ऱ थ्योरी और 15ऱ सॉफ्ट स्किल शामिल हैं। यह पाठ्यक्रम सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र नौकरी पाने के लिए पूरी तरह सुसज्जित हों।

जीएचसीएल फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री एन. एन। राडिया ने कहा, ''हमारा ध्यान जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनमें सिदी समुदाय सहित ग्रामीण युवाओं के जीवन को बदलने और सशक्त बनाने पर है। हम कौशल वृद्धि और स्थायी आजीविका विकल्प प्रदान करके क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। महत्वाकांक्षी युवा महिलाओं का समर्थन और जागरूकता बढ़ाकर, हम एक सहायक वातावरण बना रहे हैं जहां वे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से विकसित हो सकें।'

जीएचसीएल फाउंडेशन सिदी समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। 30 महिलाओं सहित 34 सिदी युवा कौशल विकास पाठ्यक्रमों में शामिल हुए हैं। फाउंडेशन अपने प्रयासों से सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

भूटान नरेश और प्रधानमंत्री का अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत

गांधीनगर 22 जुलाई : गुजरात के तीन दिवसीय दौरे के दौरान अहमदाबाद पहुंचे भूटान नरेश श्री जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक तथा प्रधानमंत्री श्री शेरिंग तोबगे का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया।

इस अवसर पर प्रोटोकॉल मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा, अहमदाबाद की महापौर श्रीमती प्रतिभा जैन, भूटान में भारत के राजदूत श्री सुधाकर दलेला, राज्य के मुख्य सचिव श्री राज कुमार, राज्य पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, विदेश मंत्रालय के अनुराग श्रीवास्तव, गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया।

स्वधा - जेजीआईएस उत्सव अंतर-स्कूल साहित्यिक और खेल प्रतियोगिता

जुलाई 2024

शैक्षणिक कार्यक्रमों में एक जीवंत गौरव, 'स्वधा - जेजीआईएस फेस्ट 2024 (एक अंतर-स्कूल साहित्यिक और खेल प्रतियोगिता) पांच साहित्यिक और पांच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सवर्णा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा जुलाई, 2024 को स्कूल परिसर, अहमदाबाद में 8:00 बजे से किया गया था। अपराह्न 1:00 बजे तक. इसने एक उत्कृष्ट अनुभवात्मक शिक्षण मंच प्रदान किया। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 21 स्कूलों के 515 विद्यार्थियों के साथ-साथ विभिन्न स्कूलों के शिक्षकों ने भी उत्साह दिखाया।

इस उत्सव में सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। और यह आयोजन उनकी योग्यता और कौशल को प्रदर्शित करने का जरिया बन गया. प्रत्येक स्कूल के छात्र अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए एक अनूठा प्रदर्शन करने में सक्षम थे।

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रगटय ने की. प्राचार्य ने युवा प्रतिभाशाली छात्रों को जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने और असफलताओं को जीवन के अवसरों के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को विकास के अवसर खोजने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

जेजीआईएस के युवा प्रतिभाशाली छात्रों को न्यायाधीशों द्वारा पुरस्कृत किया गया और सभी छात्रों को प्रतियोगिता में भाग लेने के प्रमाण पत्र दिए गए।

यह प्रतियोगिता सभी छात्रों के लिए एक समृद्ध अनुभव के साथ एक यादगार कार्यक्रम बन गई।

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने 1:1 बोनस इश्यू की सिफारिश की

सूरत, 22 जुलाई, 2024: भारत में एयरेटेड ऑटोक्लेव्ड कंक्रीट (एएसी) ब्लॉक, ब्रिक्स और पैनल के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बॉर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ने 19 जुलाई, 2024 को हुई बैठक में 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने की सिफारिश की है। बोर्ड ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को रु. 30 करोड़ तक बढ़ाने जिसमें रु. 2 प्रति शेयर के 15 करोड इक्विटी शेयर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जो सदस्यों और नियामक अधिकारियों की मंजूरी के अधीन है।

कंपनी ने अपनी बोर्ड बैठक में 1:1 के अनुपात में बोनस इक्विटी शेयर जारी करने पर विचार किया और सिफारिश की, यानी कंपनी रिकॉर्ड तिथि के अनुसार शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक रु. 2 के मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए रु. 2 का एक बोनस इक्विटी शेयर जो गुरुवार, 29 अगस्त, 2024 को होने वाली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। बोनस इश्यू के लिए रु. 28.31 करोड़ के फ्री रिजर्व का उपयोग किया जाएगा। बोनस इश्यू का उद्देश्य मौजूदा शेयरधारकों को पुरस्कृत करना, तरलता बढ़ाना और शेयरधारक आधार का विस्तार करना है।

बोनस इश्यू के बाद कंपनी की पेइड-अप शेयर कैपिटल बढ़कर रु. 28.31 करोड़ हो जाएगी, जो रु. 2 प्रति शेयर के 14,15,75,750 इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी। संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन, बोनस शेयर बोर्ड अनुमोदन की तारीख से 2 महीने के भीतर यानी 18 सितंबर, 2024 को या उससे पहले जमा किए जाएंगे।

बिगब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के चेयरमैन श्री नारायण साबू ने कहा, ''हमारी कंपनी एएसी ब्लॉक उद्योग में बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। इसके अलावा, हमारे वफादार शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और तरलता को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड ने एक बोनस इश्यू की सिफारिश की है। यह कदम हमारे इक्विटी आधार को बढ़ाएगा और निरंतर विकास का समर्थन करेगा। हम निरंतर गति का अनुमान हैं और आने वाले वर्षों में और उपलब्धियों की आशा करते हैं।''

राजकोट रेल मंडल के 4 स्टेशनों को प्राप्त हुआ 'ईट राइट स्टेशन' सर्टिफिकेट

राजकोट रेल मंडल के 4 रेलवे स्टेशनों को हाल ही में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया **(FSSAI)** द्वारा **`Eat Right Station'** सर्टिफिकेट दिया गया है। इन स्टेशनों में राजकोट, जामनगर, सुरेन्द्रनगर और द्वारका शामिल हैं।

"ईट राइट स्टेशन" का यह प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा उन स्टेशनों को दिया जाता है जो स्वच्छता, साफ-सफाई के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हैं। यह सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं जैसे बुनियादी स्वच्छता बनाए रखने, भोजन के प्रबंधन के लिए विक्रेताओं को प्रशिक्षित करना, खाद्य नमूनों की जाँच करना और उनकी रिपोर्ट प्राप्त करना, सभी प्रक्रियाओं का ऑडिट करना, जिला नामित अधिकारी जैसे राज्य प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना और इदएर्ऊंण (खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन) प्रशिक्षण के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के साथ समन्वय करना। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद राजकोट मंडल के 4 स्टेशनों को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रतीक है जो विश्वसनीयता और ग्राहक विश्वास को बढ़ाता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि आप जो खाना खाते हैं वह 'सुरक्षित और पौष्टिक' है।

राजकोट मंडल रेल प्रबंधक श्री अश्वनी कुमार ने बताया कि राजकोट मंडल के सभी स्टेशनों पर खानपान की गुणवत्ता का समुचित ध्यान रखा जा रहाहै ताकि रेल यात्रियों को साफ-सुथरा और सेहतमंद खाना मिल सके।

अहमदाबाद मण्डल ने 720 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त किया

पश्चिम रेलवे का अहमदाबाद मण्डल अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रयास कर रहा है और इसकी गति को बनाए रखा है। मण्डल रेल प्रबंधक श्री सुधीर कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में अहमदाबाद मण्डल ने जून 2024 में 720.52 करोड़ रुपये के कुल राजस्व के आँकड़े को पार किया। जो पिछले वर्ष जून 2023 के 677.11 की तुलना में 6.41ऱ से अधिक है।

बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के सक्रिय विपणन प्रयास एवं नीतियों में व्यापक बदलाव से यह उपलब्धि हासिल करने में सफलता मिली है। बिजनेस डवलपमेंट यूनिट अहमदाबाद ने 25 जून 2024 को पश्चिम रेलवे और बंदरगाह विकास प्राधिकरणों के कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों के साथ एक सहयोगात्मक बैठक आयोजित की। रेलवे में समग्र कंटेनर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव बिजनेस आइडिया साझा किए गए।

रेल संरक्षा में उत्कृष्ट कार्य के लिए चार रेल कर्मचारी सम्मानित

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक श्री सुधीर कुमार शर्मा ने मंडल के 04 रेल कर्मियों को सुरक्षित ट्रेन परिचालन में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए सम्मानित किया। इन रेल कर्मियों को डयूटी के दौरान उनकी सजगता एवं सतर्कता के कारण अप्रिय घटनाओं को रोकने में उनके योगदान के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री उमेश प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा-स्टेशन अधीक्षक असारवा, श्री राजेश कुमार फिटर-असारवा, श्री हिमांशु भाटी सहायक लोको पायलट-साबरमती एवं श्री धारासिंह माल फिटर-पालनपुर ने अप्रत्याशित घटनाओं जैसे ट्रैक्टर वॉटर टेंक का आगे और पीछे का एक-एक पहिया प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाने पर लोको पाइलट को वीएचएफ से जहा पर भी गाड़ी हो वही पर रोक देने के लिए कहा, ओएचई पर कुछ असामान्य धातु असुरक्षित अवस्था में है यह नोटिस किया और तुरंत ही लोको पायलट को सूचित किया, लिडिंग व्हील की प्राइमरी स्प्रिंग को टूटा हुआ देखने पर तुरंत ही जानकारी अपने पर्यवेक्षक को देना एवं तुरन्त उचित कार्यवाही करके अप्रत्याशित घटना और संभावित क्षति से बचाया है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री सुधीर कुमार शर्मा ने इन सजग सरंक्षा रेल प्रहरी की हौसला अफजाई की। और कहा कि यात्रियों की सरंक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है एवं जब रेलकर्मी अपनी डयूटी के दौरान सजगता और सतर्कता से काम करते हैं तो हमें सेफ ट्रेन वर्किंग में मदद मिलती है। हमें इन रेल कर्मियों पर गर्व है।

लेशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड रु. 49.28 करोड़ का राइट्स इश्यू 22 जुलाई को खुला

राइट इश्यू में शेयर 19 जुलाई 2024 को रु. 4.02 प्रति शेयर के बंध मूल्य की तुलना में रु. 2.8 प्रति शेयर पर पेश किए गए है

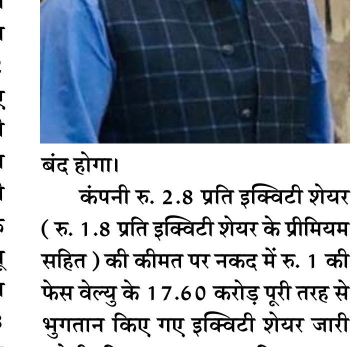

अहमदाबाद, 22 जुलाई, 2024: केमिकल और स्टील प्रोडक्ट्स के कारोबार में लगी अहमदाबाद स्थित लेशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीएसई - 533602) का रु. 49.28 करोड़ का राइट्स इश्यू 22 जुलाई, 2024 को सब्सक्रीप्शन के लिए खुला। इसका उपयोग कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, नई ऑफिस की खरीद, सामान्य पूंजी सहित कंपनी की विस्तार योजनाओं को फंड देने के लिए किया जाएगा। कंपनी का राइट इश्यू 19 जुलाई, 2024 को रु. 4.02 प्रति शेयर के बंद मूल्य की तुलना में रु. 2.8 प्रति शेयर की कीमत पर पेश किया गया है। राइट्स इश्यू 05 अगस्त, 2024 को बंद होगा।

कंपनी रु. 2.8 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 1.8 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) की कीमत पर नकद में रु. 1 की फेस वेल्यु के 17.60 करोड़ पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिसका मूल्य कुल मिलाकर रु. 49.28 करोड़ होंगा। प्रस्तावित इश्यू के लिए राइट्स एंटाइटेलमेंट अनुपात 8:5 पर तय किया गया है (यानि की रिकॉर्ड तिथि 12 जुलाई, 2024 को इक्विटी शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक 5 पूर्ण भुगतान वाले इक्विटी शेयरों के लिए रु. 1 के अंकित मूल्य के 8 राइट्स इक्विटी शेयर)। ऑन-मार्केट अधिकार अधिकारों के त्याग की अंतिम तिथि 30 जुलाई, 2024 तक है।

रु. 49.28 करोड़ की इश्यू आय में से, कंपनी रु. 10.11 करोड़ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए, रु. 6 करोड़ नई ऑफिस की खरीद के लिए, रु. 20.41 करोड़ राइट्स इक्विटी शेयरों के लिए प्रमोटर/प्रमोटर समूह के असुरक्षित ऋण के समायोजन के लिए और रु. 12 करोड का सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का इरादा रखती है।

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादक: लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोन: 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95